कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

lnL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDl : +91(11) 23387887

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

जन लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर श्री अन्ना हजारे और उनकी टीम ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री की संपादकों से बातचीत पर भाजपा अध्यक्ष की टिप्पणी..... 6

रिपोर्ट : भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा का राष्ट्रव्यापी ''जनअभियान''

दिल्ली..... 8
मध्य प्रदेश..... 13
बिहार..... 15
उत्तर प्रदेश..... 15
उत्तराखण्ड..... 15
राजस्थान..... 16

लेख

लोकपाल को कठपुतली मत बनाइए
&v#.k tVyh..... 21
काश! भारतीय राजनीति इस कड़वे सच को समझ ले
&çHkkr >k..... 23
शब्दों की बाढ़, कर्त्तव्यों का अकाल
&vEckpj.k of'k"B..... 25

अन्य

जबेरा एवं पूर्णिया विधानसभा उपचुनावों में भाजपा की जीत..... 12

संपादक के नाम पत्र

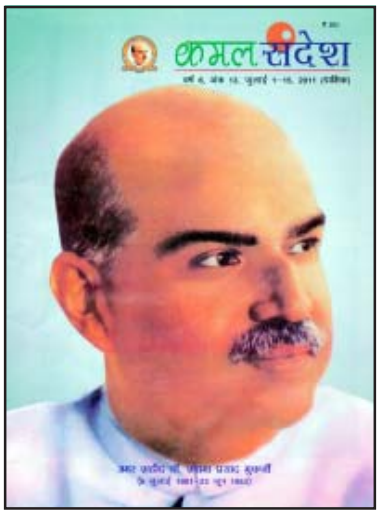

vknj.kh; lEiknd egksn;]

कमल संदेश (जुलाई प्रथम) का अंक पढ़ा। अमर शहीद डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के जीवन के बारे में जानकार देश के प्रति कुछ कर गुजरने का हौसला मिला। साथ में यह भी जाना कि किस तरह उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आपसे निवेदन है कि पत्रिका में महापुरुषों के जीवन चरित्र निरंतर प्रकाशित करते रहिए। इस अंक में 'मायाराज बना आतंकराज' रिपोर्ट भी पढ़ा। वास्तव में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगलराज स्थापित हो गया है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है। सरेआम महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं और उनकी हत्या की जा रही है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार चिंता के विषय हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह अपराधियों को सख्त सजा दे।

ohjsUnz dqekj
flafx;kgh] lhrke<+h] fcgkj

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको निरन्तर मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको अंक कोई प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

सम्पादकीय

विदेशी बैंकों में अकूत कालाधन पर भारत निर्धन

ह कैसी विडम्बना है? आखिर! भारत सरकार, जिस पर कांग्रेसनीत यूपीए सरकार पूरी तरह है सवार, क्यों नहीं खोल रही उन बैंकों का द्वार, जिसमें बंद है काले लोगों के कालेधन। भारत के सामान्य लोगों की जुबां पर यह बात चढ़ गई है कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह इस मसले पर मौन क्यों धारण किए हैं? क्यों चुप हैं देश का गृहमंत्री पी. चिदम्बरम? इसी तरह की बात श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में कही जा रही है। देश की जनता कह रही है कि अगर इन बैंकों में कांग्रेस के नेताओं की राशि नहीं है तो वे क्यों डर रहे हैं और डंके की चोट पर उन सफेदपोशों के नाम देश की जनता के सामने लाने में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार क्यों घबरा रही है? सर्वोच्च न्यायालय की सरकार को लगाई जा रही फटकार का भी भारत सरकार पर असर क्यों नहीं हो रहा? पिछले लोकसभा चुनाव में स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी एवं डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि आप हमें सरकार में पुनः लायेंगे तो हम सौ दिन के भीतर विदेशों में जमा भारत के अरबों–खरबों रुपए, जो कालेधन के रूप में जमा हैं, को वापिस लायेंगे? कांग्रेस कहे कि उसने यह वादा देश की करोड़ों जनता के सामने नहीं किया था। आज कांग्रेस चुप क्यों है? इसी कारण शक की सुई कांग्रेस की ओर जा रही है।

आज भले ही काले धन के मसले को कांग्रेस हल्के से ले पर आने वाले दिनों में उसे लेने के देने पड़ेंगे। गांव में अक्सर लोग कहते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इसी तरह कांग्रेस कब तक खैर मनाएगी आज नहीं तो कल उन्हें जनता के सामने सच को लेकर आना ही होगा। हमें आश्चर्य लगता है कि जो बात देश का आम आदमी समझ रहा है कि अगर काला धन विदेशी बैंकों में जमा है तो वह बेनाम तो होगा नहीं और जब नाम से जमा होगा तो फिर नाम जानने और बताने का अधिकार भारत को क्यों नहीं है?

कांग्रेस अगर पार्टी होती तो निश्चित ही कांग्रेस के अंदर विरोध का स्वर स्वयं फूटने लगता पर बात यह है कि कांग्रेस अब पार्टी बची नहीं, वह तो एक परिवार की पार्टी है, इसलिए वहां विरोध का स्वर तो दूर, उल्टे वहां हर कोई एक परिवार की परिवार–चालीसा पढ़ने में लगा हुआ है।

भारत एक गरीब देश है, यह अब सुनने को भारत तैयार नहीं है। भारत कैसे सुने यह बात, जब उसे पता है कि स्विस खातों में गरीब भारत के अनेक अमीरों और सफेदपोशों के धन जमा हैं। भारत उद्वेलित है। भारत का चित्त अशांत है। कांग्रेसी और उनके समर्थक गली–कूचों में उठते सवालों पर पानी छिड़कने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। कौन समझाए? कांग्रेस की स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है कि आज उनके मध्य दम से कोई यह कहने को तैयार नहीं है कि किसी भी कांग्रेसी का स्विस बैंक में पैसा नहीं जमा है। कांग्रेस की चुप्पी ही उसे संदेह के कटघरे में खड़ा करता है। वैसे तो कांग्रेस में कार्यकर्ता कम समर्थक अधिक होते हैं। पर आज तो स्थिति इतनी दयनीय है कि समर्थक तो समर्थक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताशा और निराशा के दौर में हैं। स्वयं कांग्रेसी गांव–गांव में चर्चा कर रहे हैं कि जब किसी कांग्रेसी का विदेशी बैंकों में काला धन नहीं जमा है तो फिर यह उजागर क्यों नहीं हो रहा है?

देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करना स्वयं देश की आम जनता की चिंता को व्यक्त करता है। एक सौ पन्द्रह करोड़ लोगों को जिन्हें सच जानने का लोकतांत्रिक अधिकार है, उसे भला यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह कब तक छुपाएंगे? उन्हें जनता के समक्ष सच आज नहीं तो कल रखना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो जनता उन्हें आगामी चुनाव में लोकतांत्रिक हथियार से उनके मुंह पर कोलतार पोतेगी। ■

भ्रष्टाचार और महंगाई नहीं रोक पाए मनमोहन : नितिन गडकरी

अपनी सरकार के 'कमजोर और निष्क्रिय' नहीं होने के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के दावे को अस्वीकार करते हुए भाजपा ने 29 जून को कहा कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री महंगाई और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने तथा लोकपाल विधेयक पर विपक्ष को साथ लेकर चलने में विफल रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, ''प्रधानमंत्री ने अपनी विफलताओं का बचाव करने की कोशिश की, बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन दुनिया भर में महंगाई में वृद्धि का दावा गलत है। भारत में यह खराब प्रशासन और सरकार की गलत एवं भ्रष्ट नीतियों के कारण है।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''इस सरकार में भ्रष्टाचार के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है।'' भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने 2009 लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में कहा था कि वह महंगाई पर रोक लगायेगी, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रही है।

श्री गडकरी ने कहा, ''प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से कहा था कि कीमतों को 100 दिनों में नियंत्रित कर लिया जायेगा। मार्च में एक बार फिर उन्होंने कहा कि महंगाई को काबू में किया जायेगा। लेकिन आज वह कह रहे हैं कि कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण के लिए उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि श्री सिंह इन मुद्दों पर देश की जनता से बार–बार वादाखिलाफी और विश्वासघात कर रहे हैं।

श्री गडकरी ने कहा, ''अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री परीक्षा में पूरी तरह से विफल रहे हैं। उन्होंने देश को धोखा दिया है।'' भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 70 हजार करोड़ रुपये का खाद्यान्न सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है जबकि देश की आधी आबादी की प्रतिदिन की आय 20 रुपये से कम है। श्री गडकरी ने प्रधानमंत्री के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह मनमोहन सिंह सरकार है जिसने लोकपाल के मुद्दे पर भाजपा को साथ नहीं लिया। उन्होंने कहा, ''लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के दोनों नेता महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन सरकार ने लोकपाल विधेयक पर उनसे सम्पर्क नहीं किया।'' श्री गडकरी ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष से उस समय सम्पर्क किया जब उसे लोकपाल विधेयक पर समाज के लोगों से मतभेदों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

यह पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री ने संपादकों के साथ बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष का विश्वास प्राप्त होने की बात कही है, भाजपा अध्यक्ष ने कटाक्ष किया कि 'सोनिया गांधी के करीबी' सत्तारुढ़ पार्टी के एक महसाचिव पहले ही बता चुके हैं कि किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए। श्री गडकरी समाचारों में आई दिग्विजय सिंह की उस टिप्पणी का हवाला दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। उन्होंने कहा, ''इस प्रकार का संकेत मिलने के बाद, उन्हें स्वयं इस विषय पर सोचना चाहिए। हम इस पर क्यों कुछ कहें।'' श्री गडकरी ने रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई मामले में प्रधानमंत्री की आलोचना की। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''प्रधानमंत्री की इजाजत से चार मंत्री बाबा रामदेव का स्वागत करने हवाई अड्डे पर गए। इसके कुछ दिन बाद शांतिप्रिय लोगों की भीड़ पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया।''

गौरतलब है कि संपादकों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण थी लेकिन कोई अन्य विकल्प नहीं था। पुलिस कार्रवाई को 'अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण कृत्य' करार देते हुए श्री गडकरी ने कहा, ''क्या भ्रष्टाचार और कालाधन के खिलाफ बोलना अपराध है। अब कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बाबा रामदेव के साथ जैसा व्यवहार किया गया, उसी प्रकार का व्यवहार अन्ना हजारे के साथ भी होगा।'' ■

भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा का राष्ट्रव्यापी ''जनअभियान''

loknnkrk }kjk

भारतीय जनता पार्टी ने 23 जून से 26 जून तक देश के प्रमुख केन्द्रों पर भ्रष्टाचार, कालेधन, तानाशाही के खिलाफ प्रभावी एवं राष्ट्रव्यापी ''जनअभियान'' का आयोजन किया।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि "जनअभियान" का पहला चरण डा0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर 23 जून से शुरु होकर आपातकाल की वर्षगांठ 26 जून तक संपन्न हुआ। जिसके तहत देश के प्रमुख स्थानों पर सभाएं, रैलियां, गोष्ठियां एवं जनजागरण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों में भाजपा के प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय नेताओं ने भाग लिया।

श्री नकवी ने जो कि पार्टी के केन्द्रीय कार्यक्रम एवं अभियान के संयोजक भी हैं, ने कहा कि कांग्रेस एवं उसकी केन्द्र सरकार अपने भ्रष्टाचार, कालेधन के अपराध से बचने के लिए ''धंधेबाज धर्मनिरपेक्षता एवं सुविधावादी सांप्रदायिकता, को सुरक्षा कवच बना कर अपने पाप पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं और सुनियोजित राजनैतिक चालबाजी के तहत देश से जुड़े इस महत्वपूर्ण सवाल पर भ्रम का माहौल पैदा करने की साज़िश कर कांग्रेस खुद अपनी ही चालबाजी के चक्रव्यूह में फंस चुकी है।

श्री नकवी ने कहा कि केन्द्र सरकार "चोरी और सीनाजोरी", की तर्ज पर भ्रष्टाचार, घोटालों एवं कालेधन के खिलाफ किसी भी मुहिम को "अहंकारी तानाशाह", की तरह कुचलने, बदनाम करने और भ्रम फैलाने की शर्मनाक साज़िश का तानाबाना बुनने में ज्यादा व्यस्त है ना कि इस कारण उपजे जनाक्रोश को समझ, इसका ईमानदारी के साथ समाधान करने में।

श्री नकवी ने कहा कि कांग्रेस एवं उसके नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की हर साज़िश, उसके भ्रष्टाचार के ताबूत में कील ठोक रही है और अब समय आ गया है जब देश की जनता भ्रष्टाचार एवं काले धन के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी।

श्री नकवी ने बताया कि भ्रष्टाचार, कालेधन एवं बर्बर तानाशाही के विरुद्ध इस "जन अभियान" का दूसरा चरण जुलाई से अगस्त के बीच होगा। जिसके तहत चौक, चौराहों चौपालों, गांव–गली मुहल्लों तक "जन अभियान" को ले जाया जायेगा, जिसके तहत "भ्रष्टाचार विरोधी पंचायतें", "कालाधन वापस लाओ चौपालें", "लूट पर छूट", नुक्कड नाटक "जन–जन की आवाज", गीत कार्यक्रम "भ्रष्टाचार के भागीदार", नामक प्रदर्शनियां आयोजित की जायेंगी, शहरी क्षेत्रों में "भ्रष्टाचार केसरी", हास्य–व्यंग कवि सम्मेलनों का आयोजन भी किया जायेगा।

हम यहाँ भ्रष्टाचार, कालेधन एवं बर्बर तानाशाही के विरुद्ध विभिन्न राज्यों में भाजपा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों के समाचार प्रकाशित कर रहे हैं:–

'असहाय प्रधानमंत्री के कारण देश भारी कीमत चुका रहा है' : आडवाणी

अमर शहीद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 58वें बलिदान दिवस पर 23 जून को दिल्ली भाजपा ने तालकटोरा स्टेडियम में एक विशाल जनसभा कर केन्द्र और दिल्ली की भ्रष्ट तथा तानाशाह कांग्रेस सरकारों को उखाड़ फेंकने का संकल्प किया। अंदर और बाहर खचाखच भरे स्टेडियम में कार्यकर्ताओं को सर्वश्री लालकृष्ण आडवाणी, अनंत कुमार, विजेन्द्र गुप्ता, प्रो. मल्होत्रा ने सम्बोधित किया। कार्यकर्त्ताओं में इतना उत्साह था कि अपने नेताओं के भाषण के बीच में वे गगनभेदी नारे लगाते हुए कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आवाह्न कर रहे थे। दिल्ली के सभी इलाकों से आम जनता के समूह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झंडे–बैनर सहित तालकटोरा स्टेडियम की ओर सभा समाप्त होने तक आते रहे। डॉ. मुखर्जी के बलिदान दिवस से ही भाजपा ने दिल्ली से सरकार बदलने के महाअभियान की शुरूआत करने की घोषणा की थी। इसके तहत आज तालकटोरा स्टेडियम में सर्वश्री लाल कृष्ण आडवाणी, अनंत कुमार, विजेन्द्र गुप्ता और प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा ने दिल्ली से जुटी विशाल जनसभा की भीड़ को सम्बोधित करके कार्यकर्ताओं के साथ संकल्प किया कि अब हर हाल में केन्द्र और दिल्ली की महाभ्रष्ट, तानाशाह और लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे .. दमन में तेरे दम है कितना देखा है और देखेंगे। जेल में तेरी जगह है कितनी देखा है और देखेंगे। वक्ताओं ने कांग्रेसनीत यूपीए को भ्रष्टतम सरकार बताया। मंच पर भाजपा राष्ट्रीय मंत्री सुश्री आरती मेहरा, श्री श्याम जाजू उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री श्री प्रवेश वर्मा ने किया। श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा दिए गए भाषण का पूरा पाठ हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं।

हम यहां पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के 58वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। वर्ष 1953 के इस दिन डा0 मुकर्जी ने भारत की एकता एवं अखंडता के लिये अपने जीवन का बलिदान दिया था।

आमतौर पर, शहीद उस व्यक्ति को कहा जाता है जो शत्रु देश के विरूद्ध लड़ते हुए युद्ध क्षेत्र में अपने जीवन का बलिदान देता है। डा0 मुकर्जी अपने स्वयं के देश में एक सरकार के विरूद्ध लड़ते हुए शहीद हुए। उनकी लड़ाई जम्मू एवं कश्मीर राज्य के भारतीय संघ में पूर्ण विलय के लिये थी। वह एक ऐसे दूरद्रष्टा थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर, जोकि सामरिक महत्व का राज्य है, को शेष भारत के साथ एक पृथक और कमजोर संवैधानिक सम्बन्धों से जोड़ने के परिणामों को पहले से भांप लिया था।

दुःख की बात है कि न तो नई दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने और न ही श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला की सरकार ने सोचा कि जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ में पूरी तरह से मिलाया जाना जरूरी है।

शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के विचार के ही विरुद्ध थे। नेहरूजी ने राष्ट्र को वे

कारण कभी भी नहीं बताये जिनकी वजह से वह इस विचार को अमली जामा पहनाने के अनिच्छुक थे और इसीलिये उन्होंने अनुच्छेद 370 के रूप में एक संवैधानिक विकृति होने की अनुमति दी थी। जहां तक शेख अब्दुल्ला की वास्तविक समस्या उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वे स्वतंत्र कश्मीर के निर्विवाद नेता बनना चाहते थे। जहां तक नेहरूजी का सम्बन्ध है, यह मामला साहस, दृढ़ता और दूरदर्शिता की कमी का मामला था।

58 वर्ष बाद भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस की स्थिति में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370, जिसे पंडित नेहरू ने स्वयं एक अस्थायी उपबंध बताया था, अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, कश्मीर में अलगाववादी ताकतें, जिन्हें पाकिस्तान में भारत विरोधी व्यवस्था द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और भड़काया जाता है, अपने इस जहरीले प्रचार को फैलाने में उत्साहित महसूस कर रही है कि जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय अंतिम नहीं था और विशेष रूप से कश्मीर भारत का भाग नहीं है।

जम्मू और कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण विलय का कार्य अधूरा :
कांग्रेस पार्टी की भूलों की भारी कीमत

हमारे देश ने विभाजन के समय नेहरूजी द्वारा कश्मीर मुद्दे का हमेशा के लिए भारत के पक्ष में समाधान करने में उनकी असफलता के लिये भारी कीमत चुकाई है। नेहरूजी द्वारा की गई भारी भूल से पूर्णतया बचा जा सकता था। आखिरकार गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल अन्य सभी रियासतों का–कुल 561 रियासतें–भारतीय संघ में विलय करने में सफल रहे। जब उनमें से कुछ ने हिचकिचाहट दिखाई या पाकिस्तान में शामिल होने की अपनी मंशा जताने का साहस किया तो पटेल ने नये–नये स्वतंत्र हुए भारत राष्ट्र की ताकत का उपयोग करके उनको उनका स्थान दिखाया। उदाहरण के तौर पर, हैदराबाद के नवाब के सशस्त्र प्रतिरोध को कड़ाई से दबा दिया गया। जूनागढ़ का शासक अपने कुत्तों के साथ पाकिस्तान भाग गया।

जम्मू एवं कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके विलय संबंधी मामला प्रधानमंत्री नेहरू सीधे तौर पर देख रहे थे। वास्तव में, ताकत और छलकपट के माध्यम से कश्मीर पर कब्जा करने के लिये 1947 में भारत के विरूद्ध पाकिस्तान द्वारा छेड़े गये पहले युद्ध से नेहरू सरकार को एक ऐसा शानदार अवसर मिला था जिससे न केवल आक्रमणकारियों को पूरी तरह से बाहर निकाला जाता अपितु पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे का हमेशा के लिये समाधान भी हो जाता।

भारत ने एक बार फिर 1971 के भारत–पाक युद्ध में कश्मीर मुद्दे का हमेशा के लिए समाधान करने का अवसर खो दिया जब पाकिस्तान न केवल बुरी तरह हारा था अपितु भारत के पास 90,000 पाकिस्तानी युद्ध कैदी थे।

अतः हमारे देशवासी यह जानते हैं कि कश्मीर समस्या नेहरू परिवार की ओर से राष्ट्र के लिये विशेष 'उपहार' है। इस 'उपहार' के नतीजे इस रूप में सामने आए हैं :–

- पाकिस्तान द्वारा पहले कश्मीर में और बाद में भारत के अन्य भागों में सीमापार से आतंकवाद फैलाया।
- पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में धार्मिक उग्रवाद फैलाना, जो बाद में भारत के अन्य भागों में फैल गया।
- हमारे हजारों सुरक्षा जवानों और नागरिकों का मारा जाना।
- सेना और अर्द्ध सैन्य बलों पर करोड़ों–करोड़ रुपयों का खर्च।
- भारत–पाकिस्तान के बीच कटु सम्बन्ध होने से विदेशी ताकतों को लाभ उठाने का अवसर मिलना।
- लगभग सारे कश्मीरी पंडितों का अपने गृह राज्य से बाहर निकाला जाना और अपनी मातृभूमि में शरणार्थी अथवा 'आन्तरिक रूप से विस्थापित' लोग बनना।

आमतौर पर, शहीद उस व्यक्ति को कहा जाता है जो शत्रु देश के विरूद्ध लड़ते हुए युद्ध क्षेत्र में अपने जीवन का बलिदान देता है। डा0 मुकर्जी अपने स्वयं के देश में एक सरकार के विरूद्ध लड़ते हुए शहीद हुए। उनकी लड़ाई जम्मू एवं कश्मीर राज्य के भारतीय संघ में पूर्ण विलय के लिये थी। वह एक ऐसे दूरद्रष्टा थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर, जोकि सामरिक महत्व का राज्य है, को शेष भारत के साथ एक पृथक और कमजोर संवैधानिक सम्बन्धों से जोड़ने के परिणामों को पहले से भांप लिया था।

डा0 मुकर्जी की राष्ट्र के प्रति की गई सेवा को कांग्रेस द्वारा नकारना

डा0 मुकर्जी ने पहले से भांप लिया था कि जम्मू कश्मीर को एक पृथक और गलत संवैधानिक दर्जा देने के भयावह परिणाम होंगे। परन्तु उन्होंने न केवल जम्मू एवं कश्मीर के भारत के

साथ पूर्ण विलय की बात सोची थी, अपितु एक बहादुर और शेरदिल वाला राष्ट्रभक्त होने के नाते उन्होंने इस विज़न को अपने निजी मिशन का रूप दिया था।

उन्होंने अपने मिशन को तीन क्षेत्रों–राजनीतिक, संसदीय और कश्मीर की धरती पर लागू करने का निश्चय किया।

पहला, अक्तूबर, 1951 में उन्होंने कांग्रेस के सच्चे राष्ट्रवादी विकल्प के रूप में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के लिये अपने संघर्ष के अलावा, जनसंघ का एजेंडा नये–नये हुए स्वतंत्र भारत के ऐसे ढंग से पुनर्निर्माण तक विस्तारित हुआ जिससे धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के इसके सभी नागरिकों के लिये समृद्धि, न्याय, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो।

दूसरा, वर्ष 1952 के प्रथम आम चुनावों में जनसंघ द्वारा पहली बार भाग लेने के बाद डा0 मुकर्जी लोकसभा में वस्तुतः विपक्ष के नेता के रूप में उभरे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस सरकार की जम्मू एवं कश्मीर के प्रति नीति का जोरदार विरोध किया, जिसका अन्य बातों के साथ–साथ यह अर्थ निकला कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कोई भी व्यक्ति कश्मीर के 'प्रधानमंत्री' की अनुमति के बिना कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकता था। कश्मीर का स्वयं का संविधान होगा, स्वयं का प्रधानमंत्री होगा और इसका अपना ध्वज होगा। इसके विरोध में डा0 मुकर्जी ने आवाज बुलंद की : "एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे।"

तीसरे, डा0 मुकर्जी ने 1953 में यह घोषणा की कि वह बिना परमिट के कश्मीर जायेंगे। 11 मई को कश्मीर में सीमापार करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और श्रीनगर के निकट एक जीर्णशीर्ण घर में नज़रबन्दी के रूप में रखा गया। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उन्हें उचित चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं की गई और 23 जून को वह रहस्यमयी परिस्थितियों में स्वर्गवासी हो गये। डा0 श्यामा प्रसाद को 11 मई, 1953 को कश्मीर में दाखिल होने पर गिरफ्तार किया गया था।

यद्यपि अनुच्छेद 370 को अभी तक रद्द नहीं किया गया, तथापि, जम्मू कश्मीर पर केन्द्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करने के रूप में हुई उपलब्धियां डा0 मुकर्जी के प्रत्यक्षतया संघर्ष और उनके बलिदान के परिणामस्वरूप ही हैं।

इस घटना के बाद से परमिट प्रणाली को रद्द कर दिया गया और राष्ट्रीय तिरंगा राज्य में फहराया जाने लगा।

जून, 1953 में डा0 मुकर्जी के बलिदान के बाद ही राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और सी.ए.जी. का प्राधिकार जम्मू एवं काश्मीर राज्य पर विस्तारित किया गया।

यह बड़े शर्म की बात है कि भारत की एकता और अखंडता के लिये डा0 मुकर्जी के बलिदान का इतिहास स्कूल और कालेजों में हमारे छात्रों को पढ़ाया नहीं जाता।

हमारी शिक्षा प्रणाली और सरकार–नियंत्रित मास–मीडिया नेहरू परिवार के योगदान की महिमा तो गाता है, परन्तु अन्य राष्ट्रभक्तों, जैसेकि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार पटेल, गोपीनाथ बारदोलाई, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, हिरेन मुखर्जी, ए. के. गोपालन और निश्चय ही डा0 मुकर्जी द्वारा किये गये संघर्षों और बलिदानों को या तो जानबूझकर कम आंकती है या अनदेखा करती है।

आज मैं वह दो बातें कहना चाहूंगा जो डा0 मुकर्जी की सदाबहार विरासत से सम्बन्धित है।

बड़े दुःख की बात है कि आज कांग्रेस एक ही परिवार का जागीर बन गई है। प्रधानमंत्री का पद या तो किसी मनोनीत व्यक्ति या नेहरू परिवार के किसी सदस्य के लिए आरक्षित है। कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा मनोनीत एक कमजोर और असहाय प्रधानमंत्री के कारण भारत भारी कीमत चुका रहा है। अब कांग्रेस के भीतर एक नई मांग की जा रही है कि नेहरू वंश के किसी व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाल लेना चाहिए। भारत में एक कमजोर प्रधानमंत्री अथवा अनुभवहीन प्रधानमंत्री द्वारा सरकार नहीं चलाई जा सकती।

प्रधानमंत्री को प्रणव मुखर्जी के कार्यालय में जासूसी के मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

पहला, जिस तरीके से कांग्रेस भारत की राजनीति और समाज का ध्रुवीकरण कर रही है वह बहुत ही खतरनाक है। एक समय था जब कांग्रेस एक ऐसा विशाल प्लेटफार्म था जहां पर सभी प्रकार के राष्ट्रभक्तों का सम्मान किया जाता था। वास्तव में महात्मा गांधी के कहने पर ही डा0 मुकर्जी, जो उस समय हिन्दू महासभा से संबंध रखते थे, और डा0 बी. आर. अम्बेडकर, जो कांग्रेस के कट्टर आलोचक थे, इन दोनों को स्वतंत्रता के

बाद पंडित नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।

बड़े दुःख की बात है कि आज कांग्रेस एक ही परिवार का जागीर बन गई है। प्रधानमंत्री का पद या तो किसी मनोनीत व्यक्ति या नेहरू परिवार के किसी सदस्य के लिए आरक्षित है। कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा मनोनीत एक कमजोर और असहाय प्रधानमंत्री के कारण भारत भारी कीमत चुका रहा है। अब कांग्रेस के भीतर एक नई मांग की जा रही है कि नेहरू वंश के किसी व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाल लेना चाहिए। भारत में एक कमजोर प्रधानमंत्री अथवा अनुभवहीन प्रधानमंत्री द्वारा सरकार नहीं चलाई जा सकती।

हमारा देश संप्रग सरकार के कुशासन को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता।

संप्रग सरकार के बीच विद्यमान अव्यवस्था और कुचक्र का इस से बड़ा द्योतक और क्या हो सकता है कि वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जांच के लिए कहते हैं कि पता लगाया जाए कि उनके कार्यालय में किसने और कैसे जासूसी की!

सरकार में कुछ भारी संदेहास्पद घटनाक्रम घट रहा है। इस अति गंभीर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री को अपना मौन तोड़ना चाहिए और राष्ट्र को यह बताना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ और उसका उत्तरदायी कौन है?

विपक्ष की एकता को मजबूत करना समय की पुकार

विपक्ष को संप्रग सरकार को घेरने के लिए एक के बाद दूसरा मुद्दा मिल रहा है।

डा0 मनमोहन सिंह सरकार का यह कहना है कि आवश्यक वस्तुओं की आकाश छू रही कीमतों को कम करने के लिए उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है।

डा0 मनमोहन सिंह की सरकार का यह कहना कि उसके पास भ्रष्टाचार, जो गत 7 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व ऊचांईयों पर पहुंच गया है, को कम करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है।

जब बाबा रामदेव जैसे एक सम्मानित साधु ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर नई दिल्ली में, रामलीला मैदान में एक शांतिपूर्ण प्रतिरोध करके यह मांग की कि सरकार गुप्त विदेशी बैंक खातों में जमा अवैध भारतीय धन को वापस लाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करे तो सरकार ने आधी रात को बर्बरतापूर्ण पुलिस कार्रवाई करने के आदेश दे दिये।

इन सबसे सरकार के समक्ष पेश आ रहे बड़े–बड़े मुद्दों का समाधान करने में सरकार की अरूचि, अक्षमता, असहिष्णुता और घमंड का पता चलता है।

इससे यह भी पता चलता है कि अब सत्ता के अनेकों केन्द्र सरकार को चला रहे है और प्रधानमंत्री एक मूक दर्शक बन कर रह गए है।

अब समय आ गया है कि इस सरकार के खिलाफ संसदीय और लोकप्रिय संघर्षों – दोनों को तेज़ किया जाना चाहिए।

गैर–कांग्रेस पार्टियों को पहली लोकसभा के अनुभव से कुछ सीखना चाहिए, जब डा0 मुकर्जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा गठन करने की पहल की थी, जो गठबंधन की राजनीति में एक बहुत बड़ा अनुभव था। यह 1998 में बने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए एक आगाज़ था।

भाजपा के पास अपने आपको मजबूत बनाने और राजग को भी मजबूत बनाने का एक अवसर है और इसके लिए उसकी जिम्मेदारी भी है।

वास्तव में, राजग के अलावा, सम्पूर्ण विपक्ष को कांग्रेस के कुकृत्यों का पर्दाफाश करने के लिए संसद में एक समन्वित कार्य योजना बनानी चाहिए। संसद का आगामी मानसून सत्र सरकार को घेरने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा।

पाकिस्तान के साथ वार्ता : २६/११ के मुकदमे के बारे में भारत की मांग को कमजोर करना

आज मेरा दूसरा मुद्दा पाकिस्तान के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता से संबधित है।

यह जानकर दुःख होता है कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने पाकिस्तान को यह बताया है कि भारत अभी तक पाकिस्तान के साथ हुई वार्ता प्रक्रिया से पूर्णतया संतुष्ट है और विदेश सचिवों के बीच वास्तविक अपेक्षाओं के साथ वार्ता का अगला दौर करने जा रही है।

भारत सरकार अब पाकिस्तान से 26/11 के मुबंई मुकदमें को संतोष–जनकरूप से बंद करने के लिए पाकिस्तान से मांग कर रही है।

ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रग सरकार विदेशी ताकतों के दबाव के आगे झुक गई है और पूर्व की अपनी इस मांग को छोड़ दिया है कि पाकिस्तान को अपनी भूमि पर आतंकवाद के ढांचे को पूरी तरह और हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए और अपनी निष्ठा के प्रमाण के रूप में मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल सभी दोषियों को शीघ्र ही दंडित किया जाना चाहिए।

अभी तक पाकिस्तान सरकार ने ऐसा एक भी विश्वसनीय कदम नहीं उठाया है जिससे यह पता चल सके कि वह 26/11 के आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध

कार्रवाई करने में गंभीर है। सभी उपलब्ध साक्ष्यों से यह पता चलता है कि पाकिस्तान की सत्तारूढ़ व्यवस्था में विद्यमान तत्व इन आतंकी हमलों की योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने में शामिल थे।

अब, अचानक भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर पर वार्ता के अगले दौर के लिए अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। मुंबई हमलों में शीघ्र और विश्वसनीय मुकदमा चलाने की अपनी मांग पर दृढ़ता से डटे रहने के बजाय सरकार पाकिस्तान से जो चाहती है वह मामले को ''संतोषजनक तरीके से बंद करना'' है।

संप्रग सरकार मामले को संतोषजनक ढंग से बंद करने के बारे में कैसे बात कर सकती है जबकि पाकिस्तान ने संतोषजनक ढंग से जांच आरंभ करने और मुकदमा चलाने के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई है।

स्पष्टतया, पाकिस्तान से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी की कायरतापूर्ण अकुलीन परंपरा, जो स्वतंत्रता के शुरूआती वर्षों में कश्मीर के मामले में शुरू हुई थी, आज भी जारी है।

राष्ट्र को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि सरकार कश्मीर मुद्दे पर कोई चोरी छिपे सौदा न कर पाए।

हम भाजपा के लोग डा0 मुकर्जी का बलिदान दिवस मनाते समय राष्ट्र के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को फिर से दोहराते हैं, चाहे वह राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की बात हो, लोकतंत्र को बचाने की बात हो अथवा लोगों के कल्याण की बात हो। ■

जबेरा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की

मध्यप्रदेश में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने जबेरा विधानसभा उपचुनाव जीतकर तीन लगातार उपचुनाव में जीत की हैट्रिक बनाई। भाजपा प्रत्याशी दशरथ लोधी ने कांग्रेस प्रत्याशी तान्या सालोमान को 11,738 मतों से पराजित कर कमल का फूल खिलाया।

जबेरा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर पं. दीनदयाल परिसर प्रदेश कार्यालय पर आतिशबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर बधाईयां दीं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने पं. दीनदयाल परिसर में जबेरा उपचुनाव की जीत को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और क्षेत्र की जनता के समर्थन की जीत है। विकास की जनकल्याण कार्यों पर जनतांत्रिक मोहर है। मैं मानता हं कि इस विजय से हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेगी।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद श्री प्रभात झा ने कहा कि यह जीत पार्टी की जबेरा की जनता में स्वीकार्यता की जीत है। यह जीत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तन्मयता और उनमें व्याप्त एकता की जीत है, यह जीत मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की लोकप्रियता की जीत है। प्रभात झा ने कहा कि जबेरा उपचुनाव की जीत कांग्रेस की अलोकप्रियता को प्रदर्शित करती है, उन्होंने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में हो रहे धर्मान्तरण में यह उपचुनाव क्षेत्र भी प्रमुख केंद्र था। ■

पूर्णिया उपचुनाव में भाजपा फिर जीती

पूर्णिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की। दिवंगत विधायक राजकिशोर केसरी की पत्नी और भाजपा प्रत्याशी श्रीमती किरण केसरी ने चुनाव में भारी मतों से जीत का परचम लहराया।

उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामचरित यादव को 23655 मतों से पराजित किया। किरण केसरी को कुल 53732 वोट मिले वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को कुल 30067 वोट प्राप्त हुए। ■

देश की विकट स्थिति के लिये केन्द्र सरकार जिम्मेदार : राजनाथ सिंह

Hkkरतीय जनता पार्टी द्वारा 28 जून को कृष्णपूरा छत्री पर कांग्रेस की केन्द्र सरकार के कार्यकाल में रिकार्ड तोड़, भ्रष्टाचार, बढ़ती मंहगाई व विदेशी बैंकों में जमा भारतीय भ्रष्टाचारियों का कालाधन वापस

देश में लाने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्री अनंत कुमार एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा की उपस्थिति में विशाल आमसभा संपन्न हुई। आमसभा का शुभारंभ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्री अनंत कुमार एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा, उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्यमंत्री श्री महेन्द्र हार्डिया, महापौर श्री कृष्णमुरारी मोघे, ने भारत–माता, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी व पं. दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया।

इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं जो दृश्य देख रहा हूं ऐसा दृश्य शायद ही किसी महानगर में देखने को मिले। यहां बड़ी संख्या में हिन्दू, मुस्लिम, सिख व ईसाई भी उपस्थित है। मैं जातिवाद के आधार पर राजनीति करने वालों से कहना चाहता हूं कि लघु भारत देखना है तो इंदौर आयें। मैं नगर इकाई को बधाई देना चाहता हूं कि जिसने इस आयोजन को इतनी बड़ी संख्या में किया है। भारत संकट के दौर से गुजर रहा है भारत को बचा लो, हमारा देश केवल विकट आर्थिक परिस्थितियों से ही नहीं गुजर रहा है बल्कि आंतरिक व बाह्य परिस्थतियां भी विकट हैं पड़ोसी देशों ने भारत को चारों ओर से घेर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि होना चाहिए वह नहीं है। जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिये केन्द्र की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। भारत विश्व के गरीब देशों में गिना जाता है। एक ओर देश की 95 करोड़ जनता ऐसी है जो 20 रूपये प्रतिदिन कमाती है तो दूसरी ओर प्रतिदिन 600 रूपये की आमदनी वाले लोगों की आमदनी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। देश में कुछ लोग करोड़पति से अरबपति बन गये है और कुछ गरीबी में जी रहे है यह विषमता सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न हुई है। क्या भ्रष्टाचार और कालेधन को वापस भारत में लाने की मांग करना अपराध है, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। भारतीयों के गाढ़े पसीने की कमाई भारत में आना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर बाबा रामदेव दिल्ली के रामलीला मैदान में सत्याग्रह किया। लेकिन केन्द्र सरकार के इशारों पर उन पर हमला किया गया। जो असंवैधानिक है। सर्वप्रथम भ्रष्टाचार के मुददे को भाजपा ने संसद के दोनों सदनों में उठाया, कामनवेल्थ खेलों में 11000 करोड़ का बजट पारित हुआ जो बढ़कर 71 हजार करोड़ हो गया। श्रीमती सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन उनके

कानों में जूं तक नहीं रेंगी। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कामनवेल्थ घोटाला और मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को शहीदों के फ्लैट देकर आदर्श सोसायटी घोटाले को जन्म देने वाली कांग्रेस के शासन में आंतरिक अनुसंधान विभाग में भी घोटाला हो गया। जब यह बात प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाई गई तो वह कहते है कि मेरी जानकारी में नहीं है। इसी भ्रष्टाचार के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है।

क्या यह सच नहीं है कि लगातार 6 वर्षों तक मंहगाई को बांधे रखने में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजग सरकार सफल सिद्ध हुई। जब अटलजी की नेतृत्व वाली राजग सरकार लगातार 6 वर्षों तक कीमतें बांध सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं? जब–जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो महंगाई साथ लाती है और केन्द्रीय मंत्री बयान देकर कहते है कि वैश्विक मंदी की स्थिति है। जब यह बात सफल नहीं हुई तो तर्क दिया जाता है कि देश में विकास तेज गति से बढ़ रहा है।

लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, विकास दर बढ़ रही है। इसलिये मंहगाई बढ़ रही है, लेकिन अटलजी के शासनकाल में देश की विकास दर 3 प्रतिशत से बढ़कर 8.5 प्रतिशत तक पहुंची, उसके बावजूद मंहगाई को बांधे रखने में राजग सरकार सफल हुई। पेट्रोल– डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी जारी है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एल.पी.जी. पेट्रोल व डीजल के मूल्य भारत की अपेक्षा कम है। पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, चीन, बंगलादेश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें भारत की तुलना में आधी है। अंत में उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचारी केन्द्र सरकार को उखाड फेंकने का संकल्प इस सभा के माध्यम से लेते हैं और पूरे देश में जनजागरण चलायेंगे।

राष्ट्रीय महासचिव श्री अंनतकुमार ने कहा कि सोनिया गांधी और मनमोहनसिंह वाली केन्द्र की कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है जो पिछले सात वर्षों से कुशासन कर रही है। कई केन्द्रीय मंत्री तिहाड जेल में बंद है। कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसायटी घोटाला, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में लिप्त कांग्रेसी नेता जेल के अंदर है। यह यूपीए सरकार की स्थिति है। हमारे इस जन आंदोलन में कई समाजसेवी, साधु संत एवं सामाजिक संगठन भी शामिल हो चुके है।

जब बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनशन पर बैठे तो रात में कांग्रेस ने दमन चक्र चलाया। उसके खिलाफ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट पर अनशन पर बैठा। यदि रावण के दहन के लिये रामलीला, कंस के वध के लिये कृष्ण लीला तो इस भ्रष्ट सरकार को उखाड फेंकने के लिये जनलीला होगी।

प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा ने आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने मध्यप्रदेश के हृदय स्थल इंदौर को चुना है इंदौर से हम मंहगाई, भ्रष्टाचार व कालेधन के खिलाफ शंखनाद कर रहे है। नगर इकाई बधाई की पात्र है, जिसने इस आयोजन को सफल बनाया।

भाजपा ने सोनकच्छ, कुक्षी और जाबेरा उपचुनाव जीत कर हैट्रिक बनाई है। मध्यप्रदेश में भाजपा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में 2013 में सरकार बनाने की हैट्रिक बनाएगी।

उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्र सरकार को महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से बुरी तरह घिर गई है।

राज्यमंत्री श्री महेन्द्र हार्डिया ने कहा कि भ्रष्टचार के मुद्दे पर भाजपा लगातार संघर्ष कर रही है।

महापौर श्री कृष्णमुरारी मोघे ने कहा कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो या फिर टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला या फिर सीवीसी के पद पर पीजे थॉमस की नियुक्ति का मामला हो। भाजपा और राजग ने इन सभी घोटालों को राष्ट्रीय स्तर पर जोर–शोर से उठाया। अब देश की जनता के बीच भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया है।

नगर अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि हमारे लिये गौरव का विषय है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इंदौर को यह अभियान प्रारंभ करने का अवसर दिया है। मंहगाई, भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ जनता और भारतीय जनता पार्टी का एक–एक कार्यकर्ता मैदान में लड़ाई लड़ेगा।

सभा का संचालन श्री कमलेश शर्मा एवं आभार श्री माणकचन्द्र सोगानी ने किया।

अंत में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्री अनंत कुमार एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा, उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्यमंत्री श्री महेन्द्र हार्डिया, महापौर श्री कृष्णमुरारी मोघे, नगर अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुश्री उषा ठाकुर, श्रीमती अंजू माखीजा, विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता, श्री रमेश मेंदोला, श्रीमती मालिनी गौड़, श्री जीतू जिराती, प्रदेश सह–प्रवक्ता श्री उमेश शर्मा ने मशाल जलाकर मंहगाई, भ्रष्टाचार के विरुद्व संघर्ष एवं कालेधन वापस देश में लाने के संकल्प लिया और भ्रष्टाचारी दानव को जलाया गया। ■

बिहार

मनमोहन भ्रष्टाचार के संरक्षक : अनंत कुमार

केंद्र सरकार के मंहगाई, भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैए के विरोध में भाजपा द्वारा 27 जून को पटना में आयोजित 'शंखनाद समारोह' में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बिहार प्रभारी श्री अनंत कुमार ने संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार की प्रेरणास्रोत, प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह को संरक्षक और चिदंबरम सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों को उसका भागीदार होने का आरोप लगाया।

उन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल खेल मामले में जेल गए केंद्रीय मंत्री ए. राजा, कनिमोझी और कांग्रेस नेता कलमाड़ी का जिक्र करते हुए मांग की कि इनके साथ–साथ केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम, कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और पीएमओ कार्यालय के अधिकारी रहे जरनैलसिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज करना चाहिए। श्री कुमार ने कहा कि चिदंबरम को उच्चतम न्यायालय और सीएजी के समक्ष यह बताना चाहिए कि देश के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन की इजाजत कैसे दे दी।

कांग्रेस नीत केंद्र की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम के मामले में 1.76 लाख करोड़ रुपए, राष्ट्रमंडल खेल में 67 हजार करोड़ रुपए, इसरो एस बैंड घोटाले में साढ़े पांच लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक देश की जनता का विदेशी बैंकों में कालाधन के रूप में करीब साढ़े दस लाख करोड़ रुपए जमा हैं।

उत्तर प्रदेश

इतिहास दुहराने के लिए तैयार रहें भाजपा कार्यकर्ता : उमा भारती

भाजपा की वरिष्ठ नेता सुश्री उमा भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता सपा–बसपा का राज नहीं चाहती और कांग्रेस मैदान में है ही नहीं। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता '91' को दोहराने के मूड में है। सब कुछ अनुकूल है।

डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर सरस्वती विद्यामंदिर में 'काला धन और भ्रष्टाचार' विषय पर आयोजित गोष्ठी में सुश्री भारती ने कहा कि डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपना बलिदान दे दिया। कश्मीर और गोरखपुर एक जैसे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते यह इलाका अत्यंत संवेदनशील है। भाजपा के अनगिनत राष्ट्रवादी कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं लेकिन उन्हें सक्षम नेतृत्व चाहिए। पूर्वांचल में भाजपा को बड़े महंत के होश और योगी आदित्यनाथ के जोश की जरूरत है।

उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में कुछ पार्टियों के नेता खुद को पिछड़ा– दलित और अल्पसंख्यकों

का हितैषी बताते हैं लेकिन आज सारे देश में इन तीनों वर्गों की सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश में है। जानबूझकर सेकुलर–नान सेकुलर की एक बहस खड़ी कर दी गई है। गो हत्या, रामजन्मभूमि, धारा–370 जैसे मुद्दों को नान सेकुलर करार दिया गया। गुजरात की तरक्की इस बात का सबूत है कि जो राम में आस्था रखने वाली सरकार ही रामराज्य की स्थापना कर सकती है। भाजपा वही रामराज्य उत्तर प्रदेश में लाना चाहती है। रामराज्य का सीधा सा मतलब सस्ता अनाज, सस्ता इलाज, सस्ता कपड़ा, सस्ता मकान और जिन्दगी का कीमती होना है।

उत्तराखंड

राजनाथ ने साधा सोनिया और मनमोहन पर निशाना

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में पेट्रोल दामों में बढ़ोत्तरी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं।

श्री सिंह 8 जुलाई को हरिद्वार में भाजपा द्वारा आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र में कांग्रेसनीत सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह नाकाम

साबित हुई है। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी यह झूठ बोल रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में बढ़ोतरी के चलते देश में इनके दामों में बढ़ोतरी की गयी है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 13 महीनों के दौरान 7 बार तेल के दामों में बढ़ोतरी की और इसी के चलते अब पेट्रोल के दाम 68 रूपये प्रति लीटर हो गये

हैं जबकि डीजल, मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस के दामों में भी बेतहाशा बढोतरी हुई है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में पेट्रोल के दाम मात्र 47 रूपये प्रति लीटर है। उन लोगों ने बडी ही खूबी से इनके दामों को नियंत्रित कर रखा है।

श्री सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना करते हुये कहा कि वह एक अर्थशास्त्री हैं लेकिन देश के अर्थतंत्र पर उनकी पकड़ कमजोर हो गयी है। केन्द्र सरकार देश में महंगाई तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में नाकाम रही है।

उन्होंने कहा कि आज यह हालत हो गयी है कि आम आदमी पूरी तरह से बेबस हो गया है। बढ़ती मंहगाई ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है महंगाई तथा मुद्रास्फीति में इजाफा होता है, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा।

उन्होंने कहा कि देश में गरीबी और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा काले धन के चलते बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि देश के राजनेताओं, नौकरशाहों तथा औद्योगिक घरानों का केवल स्विट्जरलैंड के बैंकों में करीब 1474 अरब डालर जमा है।

श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार काले धन को वापस देश में लाने के लिये कतई गंभीर नहीं है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने इस अवसर पर केन्द्र सरकार पर उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में राज्य को वर्ष 2013 तक के लिये विशेष औद्योगिक पैकेज दिया गया था, जिसे मौजूदा यूपीए सरकार ने घटाकर वर्ष 2010 तक कर दिया जिससे राज्य को अरबों रूपये का नुकसान हुआ।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य को मिलने वाले अनाज तथा गैस के कोटे को भी कम कर दिया। विभिन्न योजनाओं को स्वीकृत करने में अनावश्यक रूप से देरी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में लोगों के कल्याण के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम शुरू करने का दावा करते हुए लोगों से भाजपा को वापस सत्ता में लाने की अपील की।

राजस्थान

भ्रष्टाचार को उजागर करने का अभियान जारी रखेंगे : शाहनवाज हुसैन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री शाहनवाज हुसैन ने 23 जून को भरतपुर में कहा कि पार्टी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का अभियान जारी रखेगी। श्री हुसैन ने पार्टी की जिला इकाई की ओर से आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार ने रामलीला मैदान में निहत्थे और निर्दोष लोगों पर कहर ढहाकर लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया है।

उन्होंने कहा कि घपलों और घोटालों से घिरने के बाद केन्द्र सरकार देशवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ भी कदम उठा सकती है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के घोटालों और घपलों को उजागर करने वाले भाजपा नेताओं के फोन टेप किये जा रहे हैं। इसके बावजूद पार्टी कालेधन, मंहगाई के खिलाफ अभियान जारी रखेगी। इस मौके पर सभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा अरूण चतुर्वेदी, विधायक डॉ. दिगम्बर सिंह ने भी सम्बोधित किया। ■

रसोई गैस, डीजल तथा मिट्टी का तेल के दामों में भारी वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर

भाजपा का विरोध-प्रदर्शन

Hkkजपा दिल्ली प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं ने 25 जून को दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व में रसोई गैस, डीजल और मिट्टी के तेल के दामों में यूपीए सरकार द्वारा की गई भारी वृद्धि के विरोध में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री श्री रमेश बिधूड़ी ने की। कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को बढ़े दाम वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर बढ़े तब पुलिस ने पानी की तेज बौछारें छोड़ी और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। इसमें सुश्री आंचल दहिया, श्याम लाल जाटव सहित कई दर्जन कार्यकर्ताओं को चोटें आईं। घायल कार्यकर्ताओं का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देकर इस मूल्य वृद्धि का विरोध किया।

ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार ने रसोई गैस प्रति सिलिंडर 50 रूपया, डीजल 3 रूपया प्रति लीटर और मिट्टी का तेल 2 रूपया प्रति लीटर मंहगा कर दिया है। भाजपा दिल्ली प्रदेश दिल्ली तथा देशवासियों पर भीषण मंहगाई में इतना बड़ा आर्थिक बोझ आम जनता पर लादने का सख्त विरोधी है। इन बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद कार्यकर्ता प्रो. मल्होत्रा की अगुवाई में प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तब कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए गए तमाम बैरियर तोड़ डाले। पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर वॉटर कैनन से पानी छोड़ा। इस पर भी कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे तो उनपर लाठीचार्ज किया गया।

प्रो. मल्होत्रा ने सरकार के तानाशाही और जनविरोधी रवैये की घोर निंदा की है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि यूपीए सरकार इतनी भ्रष्ट, तानाशाह और जनहित के खिलाफ निर्णय लेने वाली हो गई है कि पहले से ही चली आ रही भीषण मंहगाई में और अधिक इजाफा करने के लिए उसने अकारण रसोई गैस, डीजल तथा मिट्टी के तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी है। ज्ञात हो कि इसके पहले एक महीने के अंदर ही जनविरोधी सरकार ने दो बार पैट्रोल के दामों में वृद्धि की थी जिससे मंहगाई 30 प्रतिशत और बढ़ गई थी। अब नयी मूल्य वृद्धि से गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बीपीएल कार्डधारक मिट्टी के तेल से अपने घरों में चिराग भी नहीं जला पाएंगे।

डीजल के दामों में जो वृद्धि की गई, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित किसान और ट्रक चालक होंगे। किसानों की लागत मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। डीजल के दामों में वृद्वि की खबर सुनकर देशभर के 12 करोड़ किसानों में घोर आक्रोश व्याप्त है। किसान पहले ही अपनी उपज का मूल्य नहीं पा रहे थे। अब खेती की लागत और बढ़ जाने से उन्हें कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कर्ज की अदायगी न कर पाने से हजारों किसान आत्महत्या करने को मजबूर होंगे।

रसोई गैस की कीमतों में सरकार लगातार वृद्धि करती जा रही है। इस बार तो उसने अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए गैस के दामों में 50 रूपए प्रति सिलिंडर की जो भारी वृद्धि की है, उससे आम आदमी की रसोई और सूनी हो जाएगी। देश के लाखों गरीब घरों में दोजून का खाना पकाने के लिए चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने दूध के दामों में पहले से ही बढ़ोतरी कर दी है इससे नौनिहालों के मुंह का निवाला भी छीनने लगा है। ताजा मूल्य वृद्धि करके जनविरोधी कांग्रेस सरकार ने साबित कर दिया है कि उसे अब आम आदमी की कोई भी परवाह नहीं है। ■

प्रधानमंत्री की निष्क्रियता से भ्रष्टाचार चरम पर : रविशंकर प्रसाद

भाजपा सांसद, महासचिव व मुख्य प्रवक्ता
श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा 30 जून, 2011 को जारी प्रेस वक्तव्य

प्रधानमंत्री ने कल सम्पादकों के एक ग्रुप के साथ बातचीत की और उनकी टिप्पणियों, विचारों और प्रत्युत्तरों को व्यापकता से प्रकाशित किया गया है। वे न केवल असंतोषजनक एवं पूरी तरह से भ्रामक हैं अपितु, निंदनीय भी हैं। आज सारा देश संप्रग सरकार में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार से बहुत ही दुःखी और आक्रोश में है। प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने लम्बे समय तक चुप्पी साधे रखी और जब वह बोले तो खुले तौर पर इसे स्वीकारने और कारगर कार्यवाही करने के बारे में देश को आश्वस्त करने के बजाय, उन्होंने कहा कि "भ्रष्टाचार के मामले मात्र भ्रामक है"। उन्होंने यह भी कहा कि "संप्रग सरकार अपने नीति संबंधी निर्णयों का मूल्यांकन करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए अनिश्चितता की जिस स्थिति से गुजर रही है उसे दूर करने की आवश्यकता है"। यह भ्रम पैदा करने का एक बहाना है।

भाजपा चाहती है कि प्रधानमंत्री निम्न प्रश्नों के उत्तर दें :

1. जब 2जी लाइसेंसों के आवंटन में भारी पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार किया जा रहा था और जब उन्होंने स्वयं तत्कालीन दूर–संचार मंत्री को 02/11/2007 को पारदर्शी तंत्र अपनाने के लिए पत्र लिखा था और जब श्री ए. राजा ने उनके निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया था, तब अनिश्चितता की किस परिस्थिति में उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते उनसे अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जबकि 1.7 लाख करोड़ (लगभग) की सरकारी धनराशि को लूटा जा रहा था?
2. अनिश्चितता की किस परिस्थिति ने उन्हें दूर–संचार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ सिविल कर्मचारियों द्वारा उठाई गई इन आपत्तियों पर ध्यान नहीं देने को मजबूर किया कि स्पेक्ट्रम, जो राष्ट्र की मूल्यवान सम्पत्ति है, को 2जी लाइसेंसों में बहुत ही कम दामों पर बेचा जा रहा है?
3. अनिश्चितता की किस परिस्थिति में उन्हें तत्कालीन दूर–संचार मंत्री ए. राजा को 26/10/2009 को निर्दोष बताने के लिए मजबूर किया जबकि सीबीआई द्वारा जांच किए जाने के आदेश 21/10/2004 और दोबारा 2010 में पहले ही दिए जा चुके थे ?
4. जब राष्ट्रमंडल खेलों में भारी पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही थी, तो उस समय फंड आवंटन को बढ़ाने, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार हुआ, की स्वीकृति कैबिनेट सब–कमेटी, मंत्रियों के ग्रुप, व्यय वित्त समिति, प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा दी गई थी। अनिश्चितता की वह कौन सी

शेष पृष्ठ 20 पर

आज सारा देश संप्रग सरकार में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार से बहुत ही दुःखी और आक्रोश में है। प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने लम्बे समय तक चुप्पी साधे रखी और जब वह बोले तो खुले तौर पर इसे स्वीकारने और कारगर कार्यवाही करने के बारे में देश को आश्वस्त करने के बजाय, उन्होंने कहा कि "भ्रष्टाचार के मामले मात्र भ्रामक है"। उन्होंने यह भी कहा कि "संप्रग सरकार अपने नीति संबंधी निर्णयों का मूल्यांकन करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए अनिश्चितता की जिस स्थिति से गुजर रही है उसे दूर करने की आवश्यकता है"। यह भ्रम पैदा करने का एक बहाना है।

संप्रग शासन में आम आदमी को महंगाई का करंट लगा : शाहनवाज हुसैन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद
सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा 25 जून, 2011 को जारी प्रेस वक्तव्य

गत 25 जून को देश की जनता लोकतंत्र के काले अध्याय के लिए याद करती है। 36 वर्ष पूर्व इसी दिवस कांग्रेस का तानाशाही चेहरा सामने आया था। 36 वर्ष बाद इसी दिवस को एक बार फिर कांग्रेस का घोर अमानवीय चेहरा देश के सामने आया है। यदि यह कहें कि आज देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। यूपीए सरकार के गलत आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप बेलगाम बढ़ती महंगाई से गांव, गरीब, किसान–मजदूर, मध्यम वर्ग आदि की आर्थिक हालात पहले से ही बदतर हो चुकी है। उस पर वर्तमान यूपीए सरकार द्वारा डीजल में 3 रूपये, केरोसिन तेल में 2रूपये और रसोई गैस में 50 रूपये प्रति सिलेंडर के दाम में वृद्धि का निर्णय महंगाई बढ़ाने वाला ही नहीं बल्कि आम जनता की पेट में लात मारने वाला, दूधमुंहे बच्चों के मुंह से निवाला छीनने वाला और गरीब जनता को दो जून की रोटी के लिए मोहताज बनाने वाला निर्णय है। कांग्रेस, जो यह कहती फिरती है कि कांग्रेस का हाथ आम जनता के साथ, आज कांग्रेस का हाथ आम आदमी की जेब से गले तक पहुंच गया है।

सरकार कहती है कि तेल के दाम पर उसका नियंत्रण नहीं है तो फिर इस संबंध में बैठक क्यों करती है? तेल के दाम में वृद्धि क्यों करती है? कांग्रेसनीत यूपीए की यह सरकार एक तरफ तो आम जनता को महंगाई का जख्म दे रही है, दूसरी तरफ यह कहकर कि यह तो मामूली वृद्धि है, उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। यह इस सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

देश के वित्त मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जो दलील पेश कर रहे हैं, उससे लगता है कि यह सरकार आम जनता के हितों का संरक्षण करने वाली एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही है। आखिर इस सरकार की प्राथमिकता क्या है – आम जनता का हित अथवा तेल कंपनियों का हित?

हम कांग्रेस को जगाने का काम कर रहे हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि आम आदमी के साथ मजाक करना बंद करे। कांग्रेस आम आदमी की बात करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। हमारी मांग है कि यह सरकार बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस ले और जनता को राहत दें।

पेट्रोलियम मंत्री एस जयपाल रेड्डी और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी सफाई दे रहे हैं कि कंपनियों के बढ़ते घाटे को कम करने के लिए ईंधनों के दाम बढ़ाये गये हैं। मंत्री महोदय को कंपनियों के घाटे की तो चिंता है लेकिन उन आम आदमियों की कतई चिंता नहीं है जिनकी दुहाई देकर वे सरकार में बैठे हैं।

सरकार के ताजा निर्णय से एक बार फिर आम आदमी को महंगाई का करंट लगा है। आखिर सरकार ने वही किया जिसकी आशंका थी। आम आदमी के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन केंद्र सरकार बेहद गरीब जनता के ईंधन यानी केरोसिन तेल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर, डीजल मूल्य में 3 रुपए प्रति लीटर और रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए प्रति सिलिंडर की बढ़ोतरी करते हुए सफाई दे रही है कि यह मामूली बढ़ोतरी है।

इस इजाफे से सिर्फ रसोई का बजट नहीं बिगड़ेगा बल्कि रसोई तक पहुंचने वाली चीजों की कीमत भी बढ़ेगी।

डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन

महंगा होगा, बस का किराया बढ़ेगा, ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा, सामान लाना ले जाना महंगा होगा, खेती महंगी होगी, अनाज महंगा होगा, सब्जी–फल महंगे होंगे, बिजली महंगी होगी, सीमेंट महंगा होगा और मकान महंगे होंगे। सरकार के इस ताजे अव्यावहारिक निर्णय का असर दूसरी चीजों के दाम पर भी पड़ेगा। मई माह में महंगाई दर 9.06 फीसदी थी जिसमें अब और इजाफा होगा और यह बढ़कर 10 फीसदी से भी ऊपर जायेगी।

यानी, सरकार का यह फैसला हर घर पर असर डालेगा। आम जनता सरकार की मजबूरी पर कितना ध्यान देगी, कहना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अर्थशास्त्र के ज्ञान का डंका पूरी दुनिया में बजता होगा, लेकिन इस फैसले ने महंगाई की मार से पहले से ही त्राहि–त्राहि कर रही आम जनता का बाजा बजा दिया है।

यूपीए सरकार के इस जन–विरोधी निर्णय के विरूद्ध भारतीय जनता पार्टी आज देश भर में सभी जिला मुख्यालय में धरना–प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज करा रहा है। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में आम जनता ने भी भागीदारी की है जो दर्शाती है कि आम जनता में गहरा आक्रोश है। हम कांग्रेस को जगाने का काम कर रहे हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि आम आदमी के साथ मजाक करना बंद करे। कांग्रेस आम आदमी की बात करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। हमारी मांग है कि यह सरकार बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस ले और जनता को राहत दें। ■

पृष्ठ 18 का शेष

परिस्थिति थी, जिसके कारण सार्वजनिक घोषणा के बावजूद डॉ० मनमोहन सिंह शुंगलू समिति की उस रिपोर्ट के आलोक में कार्यवाही करने से इनकार कर रहे है, जिसमें श्रीमती शीला दीक्षित और राज्य के उच्च अन्य अधिकारियों और केन्द्र सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विशेषरूप से किसकी आपराधिक संलिप्तता की जांच किये जाने के आदेश दिए गए थे?

5. अनिश्चितता की वह कौन सी परिस्थिति थी, जिसके चलते डॉ० मनमोहन सिंह को पी.जे. थॉमस को सीवीसी नियुक्त करने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में उन पर मुकद्दमा चल रहा था और उच्चतम न्यायालय के नियुक्ति प्रक्रिया के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाकर उस नियुक्ति को रद्द कर दिया था?
6. अनिश्चितता की वह कौन सी परिस्थिति थी, जिसके तहत डॉ० मनमोहन सिंह की सरकार ने दिल्ली के लोकायुक्त के दिल्ली सरकार के मनी श्री राजकुमार चौहान को अपने पद का दुरूपयोग करने और भ्रष्टाचार करने के लिए उन्हें हटाने के निर्णायक निष्कर्ष को रद्द करने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश की थी?
7. डॉ० मनमोहन सिंह जी ऐसी कौन सी बात है, जो आपको राष्ट्र को यह बताने के लिए रोक रही है कि वर्ष 2005 में यथा संशोधित प्रिवेंशन ऑफ मंत्री लांडरिंग एक्ट के तहत कितने भारतीयों पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है और कितने व्यक्तियों के मामले में उन विदेशी बैंकों को अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए कहा गया है, जिनमें उनके खाते हैं ?

उक्त बातें मात्र उदाहरण हैं न कि व्यापक हैं। डॉ० मनमोहन सिंह, भ्रष्टाचार 'ऐबरेशन' नहीं है बल्कि वह पूरी तरह से परिभाषित है और आपकी सरकार का निंदनीय पहलू है। अनिश्चितता की कोई परिस्थिति नहीं थी बल्कि आपके मौन, जानबूझकर कार्यवाही न करना और आप और आपकी सरकार की भारी उदासीनता के कारण सरकारी धन को व्यवस्थागत तरीके से लूटा गया कार्य था।

देश के लोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकालने का पूरा–पूरा कारण है कि डॉ० मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार स्वतंत्रता के बाद की सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार है। भाजपा और अन्य द्वारा संसद के अंदर और संसद के बाहर किए गए भारी विरोध, मीडिया के प्रभावी अभियान और उच्चतम न्यायालय द्वारा निगरानी न की गई होती, तो कोई भी कार्यवाही नहीं होती।

सीएजी की आलोचना पूरी तरह से अवांछित

प्रधानमंत्री ने संपादकों के समक्ष की गई अपनी टिप्पणियों में सीएजी के खिलाफ एक बहुत ही अवांछनीय टिप्पणी की है कि वह नीति संबंधी मुद्दे पर टिप्पणी कर रही है। यह बहुत ही खेदजनक बात है। अपने व्यापक नौकरशाही और सरकारी अनुभव वाले डॉ० मनमोहन सिंह यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि नीति के क्रियान्वयन के तरीके की जांच निश्चय ही सीएजी द्वारा की जाती है और इसे तैयार करने और संसद द्वारा इसे स्वीकृति देने की समग्र संवैधानिक प्रक्रिया है। 2जी लाइसेंसों के मामले में सीएजी में आवंटन की नीति को लागू करने में गंभीर त्रुटियों और अनियमितताओं की जांच की है। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई द्वारा की जा रही जांच में इसके अधिकांश निष्कर्षों को सही पाया गया। इसके बावजूद भी यदि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से सीएजी की आलोचना करना उचित समझा, तो यह शासन में शुचिता और औचित्य संबंधी एक गंभीर मामला है। ■

कमल संदेश

लोकपाल को कठपुतली मत बनाइए

v#.k tsVyh

Hkz ष्टाचार के खिलाफ देश में जो नाराजगी है, वह जायज है और उसकी वजह समझी जा सकती है। भ्रष्टाचार के मौजूदा प्रकरणों ने भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था से लोगों का विश्वास हिला दिया है।

भ्रष्टाचार का कैंसर तमाम संस्थानों में फैल गया है। वर्ष 2008 में संप्रग सरकार का विश्वास मत रिश्वत के जरिये दलबदल से जीता गया था। संसदीय समिति ने रिश्वत के पक्ष में व्यापक सुबूतों की अनदेखी की और राजनैतिक आधार पर बंट गई। लोकतंत्र में संसदीय जनादेश को रिश्वत के जरिये दूषित करना सबसे बड़ा अपराध है। भ्रष्टाचार को इस मामले में संसद की अवहेलना के जरिये दबाया गया। तीन साल के लगातार विरोध के बाद भी 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर कार्रवाई नहीं हुई। संसद में लगातार दबाव, मीडिया में बहसों और न्यायिक सक्रियता के बाद कुछ लोगों को कानून के शिकंजे में लाया जा सका। राष्ट्रमंडल खेल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समारोह को भी आयोजन में भ्रष्टाचार की वजह से कलंकित होना पड़ा। न्यायपालिका में मजबूत ईमानदारी के लोग होने चाहिए। जो लोग न्यायिक व्यवस्था चलाते हैं, वे आम इंसानों के बीच के झगड़ों को सुलझाते हैं। न्यायिक संस्थाएं इस आधार पर चलती हैं कि वे पक्षपात नहीं करेंगी। दुख इस बात का है कि यह आधार अब टूटता दिख रहा है। पूर्ण निष्पक्षता की अवधारणा ही खत्म हो गई है।

इसलिए जरूरी है कि समाज में जवाबदेही की व्यवस्थाओं को मजबूत और बेहतर बनाया जाए। लोकपाल ऐसी ही एक संस्था होगी, जिसके निर्माण पर लंबे वक्त से बहस चल रही है। इससे यह उम्मीद जगती है कि जवाबदेही की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी और गलत काम करने वालों को सजा मिलने से दूसरों को सबक मिलेगा।

लोकपाल बिल का जो मसौदा सरकार ने अभी पेश किया है, उसे इसी कसौटी पर जांचा जाना चाहिए।

लोकपाल चयन तथा हटाने की प्रक्रिया

इस मसौदे के मुताबिक लोकपाल में एक अध्यक्ष और दस सदस्य होंगे, इनमें से चार सदस्य न्यायपालिका से होंगे। मसौदे में लोकपाल के चयन के लिए चयन समिति का भी स्वरूप दिया गया है। दो विपक्षी नेताओं और दो न्यायिक प्रतिनिधियों के अलावा प्रधानमंत्री, लोकसभाध्यक्ष, जिस सदन के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होंगे, उसके नेता और गृह मंत्री इसके सदस्य होंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। प्रस्तावित चयन समिति में उन लोगों का आधिपत्य होगा, जो सरकार के समर्थक होंगे। सरकारी वोट बढ़ाने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी व विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष को सदस्य बनाने का प्रस्ताव है। परवर्ती लोगों में लोकपाल नियुक्ति में कोई भी तो विशेषज्ञ नहीं है।

प्रस्तावित मसौदे के मुताबिक, इस सरकारी बहुमत के सहारे लोकपाल के अध्यक्ष और दस सदस्यों का चुनाव होगा। गैर न्यायिक सदस्य वे होंगे, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र, प्रशासनिक कानून, नीति, शिक्षा, वाणिज्य, उद्योग, न्याय, अर्थशास्त्र या प्रबंधन का विशेष ज्ञान होगा। अगर सदस्य संसद या विधानसभा का सदस्य है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसी तरह, अगर वह किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य है, तो उसे पार्टी से अपने संबंध तोड़ने होंगे। इस बिल को राज्य स्तर पर भी इसी तरह लागू करने का प्रस्ताव है। चयन समिति की ऐसी अवधारणा की गई है कि इसमें राजनैतिक आधार पर नियुक्तियां संभव हैं। किसी के दोषी या निर्दोष होने की जांच एक न्यायिक या तकनीकी काम है। इसे करने वाले को सुबूतों के ढेर से गुजरकर यह फैसला करना होता है कि कोई अपराध किया भी गया है या नहीं। न्यायाधीशों या पुलिस के जांचकर्ताओं के पास ऐसा अनुभव और ट्रेनिंग होती है कि वे यह काम कर सकें। राजनैतिक लोगों या विचारधारा

के समर्थकों को शामिल करने का अर्थ है इस प्रक्रिया को ही संदेहास्पद बना देना। सिविल सोसाइटी के सदस्य भी विचारधारा के आधार पर संदेहास्पद हो सकते हैं। इस तरह, यह मसौदा ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति संभव बनाता है जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावशाली नहीं होंगे। नियुक्तियां पूरी तरह से सरकार द्वारा की जाएंगी।

अगर कोई व्यक्ति लोकपाल के आचरण या पक्षपात से असंतुष्ट है, तो सरकारी मसौदे में उसके लिए कोई इलाज नहीं है। लोकपाल को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति के सुझाव पर यानी सरकारी सहमति से ही हटाया जा सकता है। इस तरह सरकार ही किसी लोकपाल को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, कोई नागरिक नहीं। इससे भी बुरा यह है कि लोकपाल को निलंबित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सरकार को है।

इस तरह सरकारी मसौदे का प्रारंभिक विश्लेषण यह बताता है कि चयन समिति पर सरकार का प्रभुत्व होगा। चयन का आधार अस्पष्ट होगा और यह कानूनी सुबूतों को जांचकर उनके आधार पर फैसला करने की योग्यता पर आधारित नहीं होगा।

लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री

सरकारी मसौदा प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से साफ तौर पर बाहर रखता है। लोकपाल बिल में जांच की प्रक्रिया और जांच के लिए एजेंसी बनाने का भी जिक्र है। जिस व्यापक कानून के अंदर यह अपराध आता है, वह भ्रष्टाचार निरोधक कानून है। इस कानून में प्रधानमंत्री के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। अगर सीबीआई या पुलिस भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, तो प्रधानमंत्री भी उसके दायरे में आ सकता है। आमतौर पर अगर प्रधानमंत्री कोई अपराध करता है, तो उसके लिए जवाबदेही का स्तर आम नागरिक से ज्यादा होना चाहिए। प्रधानमंत्री को व्यापक राष्ट्रीय हित में सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के मामलों में ही छूट दी जा सकती है, क्योंकि इनका संबंध भारत की सार्वभौमिकता से है। इन मामलों में प्रधानमंत्री का कोई फैसला या खर्च लोकपाल या किसी दूसरी एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इन मामलों को विशेष और अलग मानने का तो तर्क है, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री किसी व्यावसायिक लेन–देन में कमीशन लेता है या रिश्वत के जरिये विश्वासमत प्राप्त करता है, तो उसे कानून से छूट क्यों मिलनी चाहिए? इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह बार–बार यह कहते रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने में कोई एतराज नहीं है। वर्ष 2001 के लोकपाल बिल में प्रधानमंत्री को सिर्फ सीमित छूट दी गई है। इसमें कहा गया है कि लोकपाल ऐसे किसी प्रकरण में जांच नहीं कर सकता, जिनमें प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप ऐसे किसी मसले से संबंधित हों, जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ता हो। राजग द्वारा बनाया हुआ बिल इस मायने में ज्यादा सही है।

अब वक्त आ गया है कि ऐसा संस्थान बनाया जाए, जो न्यायपालिका में नियुक्तियों और विश्वसनीयता के स्तर को बनाए रखे। ऐसा संस्थान एक न्यायिक लोकपाल का काम कर सकता है।

न्यायिक जवाबदेही

वर्तमान में न्यायिक जवाबदेही या तो न्यायपालिका द्वारा तय की जाती है या उसके लिए महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया उलझी हुई, लंबी और आमतौर पर प्रभावहीन है। न्यायपालिका की जांच व्यवस्था की अपनी सीमाएं हैं। भारत ऐसी स्थिति में है, जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और महाभियोग के अलावा न्यायाधीश ही किसी दागी जज की जांच करते हैं। हमने इस व्यवस्था को देख लिया है और यह नाकाम रही है। हमें कोई नई व्यवस्था तैयार करनी होगी। इसके लिए गंभीर बहस की आवश्यकता है। सिविल सोसाइटी के कई कार्यकर्ता यह कहते हैं कि लोकपाल को न्यायिक संस्थाओं की भी जांच का अधिकार होना चाहिए। एक विकल्प यह सुझाया गया है कि न्यायपालिका में नियुक्ति और जांच का अधिकार एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को होना चाहिए। राजग सरकार ने 98वां संविधान संशोधन 2003 में प्रस्तुत किया था, जिसमें न्यायिक नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्याय आयोग की स्थापना का प्रावधान है। इसके सदस्यों में न्यायपालिका का बहुमत होगा, लेकिन सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कानून मंत्री और जनता के प्रतिनिधि के रूप में एक प्रतिष्ठित नागरिक को भी रखा जाएगा। अब वक्त आ गया है कि ऐसा संस्थान बनाया जाए, जो न्यायपालिका में नियुक्तियों और विश्वसनीयता के स्तर को बनाए रखे। ऐसा संस्थान एक न्यायिक लोकपाल का काम कर सकता है। ■

(लेखक राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं)

काश! भारतीय राजनीति इस कड़वे सच को समझ ले

✍ ÇHkkr >k

Hkkरत के मानस से दूर होती जा रही भारतीय राजनीति पर गंभीर विचार करने का समय आ गया है। 'राजनीति' भारत की समस्या बन जाए तो समाधान का मार्ग कौन ढूंढेगा? आज का ज्वलंत प्रश्न है कि राजनीति समाधान है या स्वयं में एक समस्या! देश इसका उत्तर चाहता है। 'उत्तर' दिए बिना अब यह स्वप्न सा लग रहा है कि आम जन में राजनीति, राजनीतिज्ञ और राजैनतिक दलों के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो। लोकतंत्र में ऐसी स्थिति शुभ संकेत नहीं मानी जा सकती। स्थिति की भयावहता का अंदाज शायद अधिकांश राजनीतिज्ञों को नहीं हो रहा। वे जनपीड़ा से दूर दिख रहे हैं। टोकन धरना, सामान्य पत्रकार वार्ता प्रोपेगंडा से जुड़े कुछ कार्यक्रम या फिर दो घंटे की धड़पकड़ वाली राजनीति को जनता संघर्ष नहीं मान सकती। सुविधापूर्ण आंदोलन संघर्ष की परिधि में नहीं आ सकता। संघर्ष में योग भाव चाहिए। 'संघर्ष' किसी सुविधा का मोहताज नहीं होता। संघर्ष प्रेरणा बने तो शायद जनता का मन बदले। देश में राजनीति को लेकर व्याप्त जनभ्रम को जनसंघर्ष से ही तोड़ा जा सकता है। सवाल उठता है जनसंघर्ष कैसे प्रारम्भ हो? कौन प्रारम्भ करे? जनसंघर्ष सत्ता पक्ष के भीतर से उभरे या फिर विपक्ष के गर्भ से।

अंदाजा तो इसी बात से लगता है कि आज देश में कोई ऐसा नेता नहीं बचा जिसके प्रति जनता में अटूट श्रद्धा हो। यह जरूर कहा जा सकता है कि देश के अधिकांश नेताओं के प्रति जनता में अश्रद्धा का और अनास्था के भाव ने अवश्य जोर पकड़ा है। सभाओं की स्थिति यह है कि यदि नेताओं को बस या कार से लाया जाए तो दो अंकों में जनता की संख्या नहीं पहुंच पाएगी। भला हो उस हेलिकोप्टर या चौपर का जो आज भी नेताओं से ज्यादा दर्शनीय और लोकप्रिय है। अब जनता सभा में आती नहीं है बल्कि उसे साधन मुहैया कराकर, एक समय का भोजन उपलब्ध कराने की शर्त पर वह सभा सुनने कम शहर घूमने अधिक संख्या में आते हैं। आम जन में सभाओं के प्रति उदासीनता लोकतंत्र के लिए स्वस्थ तो कहा ही नहीं जा सकता। 'आयी भीड़' के जमाने गए, अब तो 'लायी भीड़' का जमाना है। यहां मजेदार मामला यह है कि 'लायी भीड़' में भी नेता अपने भाषणों से अपनी प्राण–प्रतिष्ठा तक नहीं कर पाते। उल्टे 'लायी भीड़', जिसका मन भाषण में कम, रोटी में अधिक लगा रहता है कि मुंह से जनवाणी यह निकलती है कि देश को भाषण की नहीं आचरण की जरूरत है। 'लायी भीड़' को देख नेता चिंतित नहीं हो रहे हैं। वे 'लायी भीड़' और 'आयी भीड़' में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें 'लायी भीड़' पर ही भड़ास निकालने में आनंद आता है। नेताओं को भले ही इस आशय की चिंता न हो पर भारतीय राजनीति अवश्य चिंतित है। स्थितियों को देखकर कहा जा सकता है कि अटलजी देश के उन आखिरी नेताओं में रहे जिन्हें सुनने जनता स्वयं आती थी। जनता का स्वयं सभाओं में आना सपना हो गया। सभाओं की भीड़ अब राजनीति को नापने का या माहौल को पहचानने का फैसला नहीं बचा। उसका

देश के तमाम राजनैतिक विश्लेषकों को भी विश्लेषण करने में कठिनाई होने लगी है। वे 'आयी लहर' से तो अंदाज लगा लेते थे, पर 'लायी गई लहर' से वे अंदाज नहीं लगा पाते। राष्ट्रीय स्तर पर तो स्थिति यह हो गई है कि अब राजनेताओं के घर पर आमजन नहीं खासजन या निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षेत्र के खासजन उनके घर तक पहुंचते हैं।

मुख्य कारण है कि अब 'लायी गई भीड़' सुविधाओं से जुड़ी मानसिकता से आती है न किसी सैद्धांतिक जुड़ाव से।

देश के तमाम राजनैतिक विश्लेषकों को भी विश्लेषण करने में कठिनाई होने लगी है। वे 'आयी लहर' से तो अंदाज लगा लेते थे, पर 'लायी गई लहर' से वे अंदाज नहीं लगा पाते। राष्ट्रीय स्तर पर तो स्थिति यह हो गई है कि अब राजनेताओं के घर पर आमजन नहीं खासजन या निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षेत्र के खासजन उनके घर तक पहुंचते हैं।

जब इन हालातों के भीतर झांकने की कोशिश की गई तो पाया गया कि भारतीय राजनीति में चुनाव छोड़कर अब जनसंपर्क, जनसंवाद या जन को पत्र से जोड़ने के सभी माध्यम समाप्त कर दिए गए। 'चुनाव तक आप हमारे, उसके बाद क्यों मिले प्यारे?'

जनपत्रों का जवाब सपना हो गया। एक सर्वे से ज्ञात हुआ कि जननेता के सरकारी बाबू ही उन पत्रों का सेवन कर लेते हैं। वे पत्र उन तक पहुंच ही नहीं पाते जिनके लिए वह जन लिखता है।

दूरसंचार के इस क्रांतिकारी दौर में दूरसंचार या चलित दूरभाष (मोबाइल) पर भी बहुत से नेताजी उपलब्ध नहीं होते। स्वयं फोन उठाना तो दूर जो उठाता है वह बताता भी नहीं कि किसका फोन आया था। आखिर जनता कब तक अपना उपहास उड़वाती रहेगी। राजनीति की प्रकृति में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। पहले 'सूचनाएं' कर्त्तव्य का बोध कराती थीं, अब 'सूचनाएं' स्वयं दम तोड़ देती हैं।

अधिकांश नेताओं में समाप्त हो रही संवेदनशीलता भारतीय राजनीति को निष्ठुर और निष्प्राण करती जा रही है। भारतीय राजनीति में 'मनुष्य' का ओझल होना मनुष्यता पर सवालिया निशान समान है। आखिर हम मनुष्य–मनुष्य के लिए नहीं तो फिर हम मनुष्य क्यों?

नजर डालने पर एक बात और सामने आयी। अधिकतर राजनैतिक दलों के दफ्तरों में अब सामान्य कार्यकर्ता और समर्थक नहीं पहुंच रहे हैं। अधिकांश राजनैतिक दलों के दफ्तरों का चरित्र भी बदलता जा रहा है। बहुत स्थानों पर 'साहब' का महत्व बढ़ गया। 'साहब' उसी से मिलते हैं जिससे उन्हें मिलना होता है। 'साहब' सबसे नहीं मिलते। दफ्तरों में कार्यकर्ता नहीं कर्मचारियों का बोलबाला बढ़ता गया है। राजनैतिक दलों के दफ्तर सचिवालय के बाबूओं के असंवेदनशील स्वभाव से नहीं बल्कि उस दल के कार्यकर्ताओं की संवेदनशीलता से चला करते थे। राजनैतिक दफ्तर 'संस्कार केन्द्र' हुआ करते थे। वहां लोकतंत्र की नींव कैसे मजबूत हो, इसकी बहस हुआ करती थी। अब आजकल अधिकांशतः तो दफ्तर ही साजिश के अड्डे बनते जा रहे हैं। राजनैतिक दफ्तरों का चरित्र सरकारी दफ्तरों सा होता चला जा रहा है। प्रातः 10 बजे खुलना और शाम पांच बजे बंद होना। राजनैतिक दफ्तरों को सामाजिक स्वभाव से सदैव खुला रहना चाहिए। काश! ऐसा होता।

राजनैतिक दलों में पहले मानवीय स्पर्श का महत्व था अब तकनीकी स्पर्श की अधिकता हो गई है। स्पर्श भाव से कार्यकर्ता उत्साहित होता था, अब वह तकनीकी स्पर्श से निरूत्साहित होता है। उसके मन में यह बात घर कर लेती है कि अब मैं अपने नेता से मिलने के काबिल भी नहीं बचा। काश! भारतीय राजनीति, राजनीतिज्ञ और राजनैतिक दल पीड़ा को समझ पाते।

अधिकतर निर्वाचित नेताओं के बंगलों पर कार्यकर्ता या जनता नहीं बल्कि नेताओं के रिश्तेदारों की आमद ज्यादा पायी जाने लगी है। पहले नेता का आवास जन आवास होता था। आने वालों के लिए पूरी व्यवस्था रहती थी। यही कारण है कि बंगलों पर कार्यकर्ता नहीं उनके इर्द–गिर्द घूमने वाले अधिक पहुंचते हैं।

इस सर्वे में एक बात और सामने आई है कि बंगलों पर 'भेंट और चढ़ावा' सहज स्वीकार नहीं किया जाता था। अब स्थिति यह बन गई है कि बिना 'चढ़ावा और भेंट' के भेंट करना यानि नेताजी की तौहीन करना सा हो गया है।

भारतीय राजनीति की प्रकृति में आया यह बदलाव यदि नहीं थमा तो धीरे–धीरे हमारे लोकतंत्र की कब्र खुदती चली जाएगी और एक स्थिति यह आएगी कि हम मूकदर्शक की तरह सब कुछ अपने सामने लुटते हुए देखते रहेंगे। ■

(लेखक मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद हैं)

राजनैतिक दलों में पहले मानवीय स्पर्श का महत्व था अब तकनीकी स्पर्श की अधिकता हो गई है। स्पर्श भाव से कार्यकर्ता उत्साहित होता था, अब वह तकनीकी स्पर्श से निरूत्साहित होता है। उसके मन में यह बात घर कर लेती है कि अब मैं अपने नेता से मिलने के काबिल भी नहीं बचा। काश! भारतीय राजनीति, राजनीतिज्ञ और राजनैतिक दल पीड़ा को समझ पाते।

डॉ. मनमोहन सिंह की सम्पादकों से बातचीत

शब्दों की बाढ़, कर्त्तव्यों का अकाल

✍ vEckpj.k of'k"B

पार्टी के एक महत्वपूर्ण समारोह में बोलते हुये कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने घोषणा की थी कि कांग्रेसनीत संप्रग सरकार भ्रष्टाचार पर अब सीधा प्रहार करेगी और इसका प्रमाण शब्दों से नहीं कार्यों से देगी। उन्होंने आगे कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी तो उनकी सरकार का हृदय है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह ने माना कि भ्रष्टाचार की व्यापकता पर जनता की चिन्ता जायज़ है और इस बारे में सुधारात्मक कदम उठाने और पद के दुरूपयोग को रोकने का वचन दिया।

लगता है कि शाब्दिक कौशल के यह बाण दिल के तरकस से नहीं मुख से ही निकले। वस्तुतः हमारे भाषण लिखने वाले महानुभाव एक साथ अनेक शब्दों को उछालकर उनसे खेलने के कौशल में तो माहिर होते हैं पर उन शब्दों को ठोस कार्यों में परिवर्तित करना तो केवल उन्हीं बड़े महानुभावों का कर्त्तव्य है जो उन पात्र शब्दों को वाणी प्रदान करते हैं।

कर्त्तव्य की ध्वनि शब्दों की गुनगुनाहट से कहीं प्रखर व ऊंची होती है। यदि कांग्रेस के यह दोनों दिग्गज अपने वचनों पर कायम रहते तो प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह को जनसम्पर्क की वह कसरत करने की कोई आवश्यकता न पड़ती जो उन्हें 29 जून को कुछ चुने हुये सम्पादकों के साथ बातचीत में करनी पड़ी। इसके साथ ही उन्होंने इस बातचीत का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण न कर जनता को इसे सजीव देखने के अवसर से वंचित रखा।

संसदीय जनतन्त्र के इतिहास में डॉ. मनमोहन सिंह ही ऐसे उच्च नेता हैं जो संसद के निचले सदन, लोक सभा, के लिये चुनाव में जनता से रूबरू होने की हिम्मत नहीं जुटा पाये – उस सदन की सदस्यता के लिये जिसके प्रति वह और उनकी सरकार उत्तरदायी है। इसके विपरीत वह तो गर्व से कहते हैं कि जनता ने नहीं उन्हें तो ''यह (प्रधानमन्त्री के पद का) काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने सौंपा है।'' जनता में तो डॉ. सिंह की तो कोई साख ही नहीं है और वह तो श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा प्रदत्त समर्थन के उस ग़लीचे पर खड़े हैं जिसको श्रीमती गांधी कभी भी खींच सकती है।

प्रधानमन्त्री की सम्पादकों के साथ बातचीत में तो बस शब्दों की बाढ़ थी और कारनामों का अकाल। उनके पास वायदों की भरमार थी और ठोस कार्य का अभाव। शायद ही कोई ऐसा विषय था जिस पर उन्होंने अपना मत या विचार स्पष्ट रखा हो। कालेधन पर उन्होंने पुराने ढर्रे की वही अपनी बासी बात ही दोहरा दी कि ''जो कुछ भी सम्भव है किया जा रहा है'' पर साथ यह स्पष्ट नहीं बताया कि वह सचमुच में क्या है जो उन्होंने कर दिया है।

प्रधानमन्त्री की सम्पादकों के साथ बातचीत में तो बस शब्दों की बाढ़ थी और कारनामों का अकाल। उनके पास वायदों की भरमार थी और ठोस कार्य का अभाव। शायद ही कोई ऐसा विषय था जिस पर उन्होंने अपना मत या विचार स्पष्ट रखा हो। कालेधन पर उन्होंने पुराने ढर्रे की वही अपनी बासी बात ही दोहरा दी कि ''जो कुछ भी सम्भव है किया जा रहा है'' पर साथ यह स्पष्ट नहीं बताया कि वह सचमुच में क्या है जो उन्होंने कर दिया है।

काले धन की 4 लाख करोड़ की राशि और उसके आधार पर तो उन्होंने प्रश्न लगा दिया। पर उनकी यह बात किसी के गले नहीं उतरी क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यदि यह राशि गलत है तो सरकार के पास ठीक राशि की क्या सूचना है। न ही वह यह स्पष्ट कर पाये कि उनकी सरकार के पास जिन महानुभावों के नाम हैं उनके विदेशी बैंको में खाते हैं तो उन्हें जनता के सामने उजागर करने में उनकी सरकार को क्या परेशानी है। क्या इस सूचना को प्राप्त करने का जनता को अधिकार नहीं है?

अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी में डॉ. सिंह ने कहा कि ''बहुत से मामलों में मीडिया का रोल आज आरोप लगाने वाला, अभियोजक और न्यायाधीश का भी हो गया है।'' उनके इस उद्‌गार ने उनके और कांग्रेस पार्टी के मन में

व्याप्त उस फासिस्ट मनोवृत्ति को भी उजागर कर दिया जो असहमति को सहन नहीं कर सकती। डॉ. मनमोहन सिंह ने मीडिया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की भर्त्सना कर अपनी सरकार की उस मंशा का स्पष्ट संकेत दे दिया जो जनतन्त्र के चारों स्तम्भों – कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका एवं मीडिया – को मतारोपण की जकड़ में इस कदर बांध कर रखना चाहती है कि सरकार जो भी ठीक–गलत करे यह सभी बिना अपना दिमाग़ लड़ाये बस तालियां बजाने का ही कर्त्तव्य निभायें। उन्होंने ऐसा आभास दिया मानो वह रोक व सन्तुलन की संरचना व अवधारणा में विश्वास नहीं रखते जो किसी भी जनतन्त्र की शक्ति का आधार है। यही कारण है कि जब मनमोहन सरकार में जिसे श्री पी. चिदम्बरम ''शासन–प्रशासन के घाटे'' की संज्ञा देते हैं और उस की पूर्ति के लिये न्यायालय आगे आता है तो प्रधानमन्त्री उसे न्यायालय द्वारा कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ का शोर मचाते हैं। जब सीएजी ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर बैठते हैं जो सरकार के लिये खिन्नता का सबब बनती है तो डॉ. मनमोहन सिंह सीएजी को एक 'ईमानदार' गलती और अनैतिक गलती में फर्क रखने की सीख देते हैं।

जब भी सरकार कोई गलती कर बैठती है तो उसके पास दोष मढ़ने के लिये मीडिया एक बहुत आसान साधन है। चाहे वह कोई भी घोटाला हो – राष्ट्रमण्डल खेल, 2जी स्पैक्ट्रम, आदर्श हाउसिंग या अन्य – सरकार ने शुरू में सब को एक झूठा, मनगढ़न्त, बेबुनियाद ही बताया। तब डा0 मनमोहन सिंह अपनी ही दूसरों को दी गई सीख को भूल जाते रहे कि ''तथ्य पवित्र होते हैं और उनका मान करना चाहिये''। डा0 मनमोहन सिंह व श्रीमती सोनिया गांधी अन्तिम क्षण तक तो श्री ए राजा और श्री सुरेश कलमाड़ी को ईमानदार और निर्दोष होने का प्रमाणपत्र जारी करते रहे। पर मीडिया अपने तथ्यों पर डटा रहा। सीएजी ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। न्यायालय ने हस्तक्षेप किया जिसके उपरान्त राजा और कलमाड़ी दोनों को ही जेल की हवा खानी पड़ी। पर क्या विडम्बना है कि यही डा0 मनमोहन सिंह और श्रीमती गांधी अब राजा–कलमाड़ी को जेल भेजने का श्रेय लेना चाहते हैं।

श्री मनमोहन सिंह ने एक और अनोखा तर्क प्रस्तुत किया जब उन्होंने दावा किया कि 'राष्ट्रहित' में सरकार को अनेक बार निर्णय लेते पड़ते हैं जब ''सभी तथ्य विदित नहीं होते, वह कभी विदित होंगे भी नहीं''। यह तो उनकी इस तथ्य की स्वीकारोक्ति है कि उनकी सरकार अंधेरे में ही दिशाहीन हाथ–पैर मारती फिरती है। वह हर पहलू पर विचार किये बिना ही अधपके निर्णय लेती है। डा0 मनमोहन सिंह के लिये उनकी सरकार के तथ्यपूर्व (ऐक्स–फैक्टो) निर्णय पवित्र हैं और तथ्यउपरान्त (पोस्ट–फैक्टो) के सीएजी व न्यायालय के निर्णय पाप।

सरकार तो सूचना, तथ्यों व गोपनीय बातों का संग्रहालय होती है। पर उस सरकार के बारे क्या धारणा बनाई जाये जो वैसे तो जनता के लिये सूचना के अधिकार कानून को बनाने पर गर्व करती है पर अपने ही पास जो तथ्य और सूचनायें हैं उनसे अनभिज्ञ बनती है और अपने ही विभागों से उन्हें राष्ट्रहित में अपने लिये प्राप्त करने के लिये अपने आपको अक्षम पाती और बताती है?

डा0 सिंह ने उस तुलना को खारिज किया कि उनका समय पूरा हो गया है और वह तो बस लेम–डक प्रधान मन्त्री हैं जो श्री राहुल गांधी के लिये कुर्सी को गर्म रख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके उत्तराधिकारी ढूंढने का मामला अभी कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष विचाराधीन नहीं आया है। पर उसी सांस में वह यह भी कहने से न चूके कि ''श्री राहुल गांधी में एक अच्छा प्रधान मन्त्री बन पाने की पूरी क्षमता व धारणशक्ति विद्यमान है''। इन्हीं मानदण्डों पर वह स्वयं कहां खड़े होते हैं, यह उन्होंने खुलासा नहीं किया।

उन्होंने राहुल को लाने के राग को एक ''सही भावना'' बताया और कहा कि ''युवाओं को काम सम्भाल लेना चाहिये''। पर प्रश्न तो यह उठता है कि यदि डा0 मनमोहन सिंह अच्छा काम कर रहे हैं और पार्टी उनकी कार्यकुशलता से सन्तुष्ट है तो उनके स्थान पर राहुल को लाने की बात का क्या तुक है? पर साथ ही उन्होंने अपनी इस उदारता और शिष्टता का भी परिचय दिया जब उन्होंने आगे कहा कि वह उसी क्षण पद त्याग देंगे जब पार्टी उन्हें ऐसा करने का आदेश देगी।

लोकपाल के मामले पर तो वह उलझन में ही दिखे। वह नहीं समझते कि लोकपाल कोई रामबाण है। सरकार ने अब तक अनेक अपराधों व कुप्रथाओं के निवारण के लिये सैंकड़ों–हज़ारों कानून बनाये हैं पर उन में से कोई भी रामबाण साबित नहीं हुआ है। भारतीय दण्ड संहिता भी है और अपराध भी हैं। तो उस कारण दण्ड संहिता को तो नहीं समाप्त किया जा सकता। यदि मन्त्री लोकपाल के दायरे में आ सकते हैं तो प्रधान मन्त्री क्यों नहीं? प्रधान मन्त्री भी तो मन्त्रिपरिषद् में बराबर सदस्यों में प्रथम ही तो गिना जाता है। प्रधान मन्त्री देश के कानून से परे या ऊपर नहीं हैं। फिर भी इस सच्चाई ने पूर्व में कभी भी ''अस्थिरता का कारण नहीं बना जो कभी बस से बाहर चला गया हो'' जैसा कि प्रधान मन्त्री को लोकपाल के अधीन

लाने से भयभीत कर रहा है। वह आगे कहते हैं कि प्रधान मन्त्री तो ''24 घंटे ही जन सेवक है....भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अधीन और...प्रधान मन्त्री को तो बड़ी आसानी से बर्खास्त किया जा सकता है.....आवश्यकता केवल उनके विरूद्ध संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास करने की है''। प्रधान मन्त्री ने दावा किया कि सरकार के पास ''प्रभावी व्यवस्था, बहुत प्रभावी विद्यमान है''। पर वास्तविकता तो यह है कि इसके वावजूद भी संप्रग मन्त्रियों ने 2जी व राष्ट्रमण्डल खेल जैसे अनेक घोटाले कर डाले कि आज मनमोहन सरकार भारत की भ्रष्टतम सरकारों की सूची में आ गई है।

यदि प्रदेशों में मुख्य मन्त्रियों को लोकायुक्त के अधीन कर देने से कभी कोई ''अस्थिरता का कारण नहीं बना जो कभी बस से बाहर चला गया हो'' तो प्रधान मन्त्री को लोकपाल के अधीन लाने से कैसे ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी?

प्रधान मन्त्री ने आगे दावा किया कि ''यदि एक मन्त्री जानबूझ कर एक निर्णय लेता है तो यह उसकी ज़िम्मेदारी है ... बजाये इसके कि यह कहना कि प्रधान मन्त्री ने भी इसका समर्थन किया है''। ऐसा दावा कर जाने या अनजाने में प्रधान मन्त्री संविधान के उस प्रावधान की अनदेखी कर रहे हैं जिस में कहा गया है कि मन्त्रिपरिषद् सरकार के हर कार्य केलिये सांझे तौर पर ज़िम्मेदार होगी। वह आगे कहते हैं कि मन्त्री ने बताया कि अमुक कार्य कानून के प्रावधान अनुसार है। फिर भी क्या प्रधान मन्त्री का कर्तव्य नहीं बनता कि वह इस बात से अपनी सन्तुष्टि कर ले?

जिस दिन डा0 मनमोहन सिंह प्रधान मन्त्री बने उसी क्षण से वह कीमतों और मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण कर लेने का दावा कर रहे हैं। पर पिछले सात वर्ष में हुआ इसके विपरीत है। अब कहने लगे हैं कि मुद्रास्फीति तो सारे संसार में व्याप्त है। उन्होंने डा0 रंगराजन से बात की और उनके हवाले से भविष्यवाणी की कि ''मार्च (अगले) के अन्त तक मुद्रस्फीति 6.5 प्रतिशत हो जायेगी''। पर अब तक तो उनके शब्द कभी सच साबित नहीं हुये। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास कीमतें और मुद्रास्फीति कम करने के लिये कोई ''जादू की छड़ी नहीं है'' और इसे भूमण्डलीय समस्या जता कर अपने उत्तरदायित्व से पल्ला झाड़ लिया।

जैसा कि एक कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा था, मनमोहन सरकार सिविल सोसाईटी के ''अनिर्वाचित और अनिर्वाच्य व्यक्तियों के आतंक से पीड़ित है''। वह केवल उनसे ही नहीं, वह` अध्यक्ष को छोड़ संविधानोतर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अन्य ''अनिर्वाचित और अनिर्वाच्य'' सदस्यों के आतंक से भी पीड़ित है जो चाहती है कि सरकार उनके द्वारा सुझाये कानून व सुझावों पर चुपचाप अपना अंगूठा लगा दे।

अनिश्चितता के इस माहौल में भी जब सरकार उद्देश्यहीन बन कर भटकती जा रही है तो डॉ. मनमोहन सिंह मात्र इतनी बात से ही सन्तोष किये बैठे हैं कि आज का माहौल में ''कोई भी चुनाव नहीं चाहता और आत्मपरीक्षण की स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारे ही हक में जाएगी। ■

(लेखक भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

भाजपा कच्चाथीवू मामले को संसद में उठाएगी : सुषमा स्वराज

लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने तमिलनाडु विधानसभा में पारित कच्चाथीवु की वापिसी सम्बन्धी प्रस्ताव को लोकसभा में उठाने का वायदा किया है तथा यह भी कहा कि श्रीलंका पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जाए।

श्रीमती स्वराज 26 जून को चेन्नई में एआईएडीएम के की जनरल सेक्रेटरी तथा मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता की साझा मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रही थीं। श्रीमती स्वराज ने सुश्री जयललिता से उन दो प्रस्तावों की प्रतियां भेजने का अनुरोध करते हुए कहा कि ''हम इन दोनों मुद्दों को लोकसभा में उठाएंगे।''

श्रीमती सुषमा स्वराज ने इसे शिष्टाचार भेंट बताते हुए कहा कि हम दोनों विधानसभा में सुश्री जयललिता की विजय के बाद पहली बार मिले हैं।

श्रीमती स्वराज ने पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी कीमतों पर सरकार को आम आदमी के प्रति एक संवेदनशून्य माना है। यह सरकार बार–बार आम आदमी के प्रति कल्याणकारी नीतियां बनाने का दम भरते हुए भी उसके निर्णय उन्हीं लोगों को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें दसवीं बार बढ़ाई गई हैं तो उधर मिट्टी के तेल की कीमतों के बढ़ने से गरीब लोगों पर बुरी तरह असर पड़ेगा। इसी प्रकार एलपीजी की बढ़ी कीमतें मध्यम वर्ग की महिलाओं को बुरी तरह से परेशान करके रख देंगी। ■

भारत-अमरीका के सम्बन्ध कभी नहीं बिगडेंगे : अरुण जेतली

23 जून, 2011 को श्री अरुण जेतली ने हैरीटेज फाउण्डेशन, वाशिंगटन में दिए गए भाषण के कुछ प्रमुख अंशः

jk ज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेतली ने अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध व्यापक रूप से इस बात पर निर्भर करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह का भारत के साथ व्यवहार करता है और क्या वह पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बनने से रोकने में समर्थ हो पाएगा?

भारत–पाक विदेश सचिव स्तर पर होने वाली वार्ता से पूर्व अपनी विशेष टिप्पणी में श्री जेतली ने अमरीकी श्रोताओं को पाकिस्तान को धरती से उत्पन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि किस प्रकार से समग्र वार्ता पर भारत की ओर से की गई अनेक पहल पर पाकिस्तान ने इसे विफल कर दिया।

भारत सरकार में अब तक की सभी सरकारों ने जिनमें एनडीए तथा यूपीए सरकार दोनों ने ही, निरंतर वार्ता को प्रोत्साहित करने और पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने की कोशिश की परन्तु पाकिस्तान में जिस तरह की परिस्थितियां बनती रही उनके कारण ही इन कोशिशों की नियति का निर्धारण होता रहा।

वाशिंगटन में हेरीटेज फाउण्डेशन में बोलते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता का कहना था कि सरकारी भूमिका और गैर–सरकारी भूमिका के बीच कुछ ऐसा अन्तर बना रहा जिससे आंशिक रूप से इनकी भूमिकाएं समाप्त होती चली गईं क्योंकि लश्करे–तैय्यबा और अफगान तालिबान जैसी पाकिस्तानी एजेंसियों ने आतंकवादी संगठन खड़े कर दिए।

श्री जेतली ने आगे कहा कि अब हमें निश्चित यह समझना और मानना होगा कि हमें पाकिस्तान की समग्र प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की है जिसमें उन सभी लोगों को जो भारत पर वार्ता के लिए दबाव डालते हैं कि भारत के पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध पाकिस्तान में घट रहीं घटनाओं पर निर्भर करते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के अलावा, अमरीका और पूरे विश्व को भी यह समझना होगा कि उनके अपने सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ कैसे हैं?

जिस दिन प्रेजीडेण्ट बराक ओबामा ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों को चरणबद्ध ढंग से वापस बुलाने की घोषणा की थी तो जेतली ने घोर चिंता अमरीकी फौजों के बाहर निकलने से पैदा होने वाली स्थिति पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की थी। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि ऐसा होने पर क्या उस देश में शांतिपूर्ण शासन और राजनीतिक स्थिरता रह पाएगी?

श्री जेतली ने ''आज के बदलते विश्व–व्यापी दृश्य में भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकताओं'' पर बोलते हुए भारत–अमरीकी सम्बन्धों पर विस्तृत चर्चा करते कहा कि वाजपेयी सरकार ने सम्बन्धों की पुनर्स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण शुरूआत की थी।

श्री जेतली ने महसूस किया कि पिछले दशक में आज जिस प्रकार के भारत–अमरीकी सम्बन्धों का देखने में आया है, उसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों में यात्राएं और समझ बढ़ी है और भारत में ''व्यापक द्विपक्षीय समर्थन'' का भाव बढ़ा है।

श्री जेतली ने विशेष रूप से कहा कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा होगी जिसमें भारत में आगे कभी भी किसी भी प्रकार की राजनीति बदलाव से इसमें कोई गम्भीर परिवर्तन आए। अगर कुछ भी हुआ तो यह सम्बन्ध आगे बढ़ने वाले ही होंगे।

भारत–अमरीका सिविल न्यूक्लियर सौदे पर मतभेदों के एक प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विश्व

की सबसे बड़े दो लोकतांत्रिक देशों के बीच सम्बन्धों को किसी एक खास मुद्दे की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

'न्यूक्लियर लाइबिलिटी लेजिस्लेशन' का बचाव करते हुए श्री जेतली ने अमरीकी न्यूक्लियर सप्लायर्स के भय का निवारण करने की कोशिश की और कहा कि इस विषय में निवेश करना पर्याप्त सुरक्षित रहेगा।

इस विषय पर विस्तार से बोलते हुए भाजपा सांसद श्री चंदन मित्रा ने कहा कि 'लाइबिलिटी लॉ' की किसी भी प्रकार की आलोचना पर चार बातों को ध्यान में रखना चाहिए (1) भोपाल गैस त्रासदी की पृष्ठभूमि और भारत में दिए गए अत्यंत अल्प क्षतिपूर्ति पर हुआ हुंगामा; (2) न्यूक्लियर पावर की अत्यधिक लागत; (3) भूमि अधिग्रहण पर विवाद, विशेष रूप से न्यूक्लियर संयंत्रों के लिए जैसा कि हमें जैतापुर, महाराष्ट्र में देखने में आया; और (4) सुनामी के बाद आए भूकम्प के कारण नुकसान को देखते हुए न्यूक्लियर पावर संयंत्र लगाने की पूरी बहस को फिर से खोला जाना।

श्री जेतली ने भविष्य के बारे में भी कहा कि ऐसे कुछ मुद्दे हो सकते है जिन पर भारत और अमरीका की एक जैसी राय न हो परन्तु ये सम्बन्ध कुछ क्षेत्रों में मतभेद होने पर भी अच्छे बने रह सकते हैं।

श्री जेतली ने अंत में कहा कि हमारे सम्बन्धों के व्यापक मूलाधार मजबूत है। मैं इसे लाभदायक के सम्बन्ध मानता हूं कि जहां तक हमारे क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों के निर्धारण का प्रश्न है और वृहद विश्व समुदाय का सम्बन्ध है, ये सम्बन्ध बहुत दूर तक अपने पदचिन्हों की छाप छोड़ जाएंगे।■

भाजपा शिष्टमंडल की वाशिंगटन यात्रा

बटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के आमंत्रण पर भारतीय जनता पार्टी की चार दिवसीय यात्रा 23 जून 2011 को समाप्त हो गई, जिसमें दोनों पक्षों ने भारत–अमेरीकी सम्बन्धों को बेहतर बनाने, क्षमता–निर्माण, नेतृत्व प्रशिक्षण के साथ–साथ पार्टी से पार्टी के बीच सम्पर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया।

शिष्टमण्डल का नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने किया तथा अन्य सदस्यों में श्रीमती सरोज पाण्डे, सांसद, श्रीमती वाणी त्रिपाठी (यात्रा समन्वयक), श्रीमती पूनम बेन जाट, सांसद, श्री संजय झा, एमएलसी, श्री राघव लखनपाल शर्मा, एमएलए, श्री रविन्द्र साठे, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी और डॉ. जितेन्द्र सिंह प्रवक्ता भाजपा, जम्मू और काश्मीर शामिल थे। विचार–विमर्श बहुत व्यापक रहा और शिष्टमण्डल ने यूनाइटेड स्टेट्स सिस्टम, स्टेट डिपार्टमेंट सभी वर्ग के चिंतकों तथा एकेडिमिशियनों के महत्वपूर्ण लोगों के साथ भेंट की।

शिष्टमण्डल के सदस्यों ने जिन लोगों से बातचीत की, उनमें भारत के पूर्व यूएस राजदूत फ्रैंक वाइजनर, प्रेजीडेण्ट आफ इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट लोर्न क्रेनर, पब्लिक ओपीनियन स्ट्रेटेजिज एक्सपर्ट जिम बर्टन, सेनेटर जॉन थूने, चेयरपर्सन इलीना लेहरिनन, नेशनल सिक्युरिटी कौंसिल सेनेटर डायरेक्टर माइकल न्यू बिल, प्रेजीडेण्ट आफ नेशनल फ्रेडरेशन आफ वूमेन सू लिंच, कांग्रेसमेन एड रॉयस तथा अन्य कई लोग शामिल थे। भाजपा और आइआरआई दोनों को इस वार्ता को और आगे बढ़ाने तथा रणनीति और हर ढंग से पारस्परिक रूप से एक दूसरे के साथ सहयोग करने की उम्मीद है।

इस वर्ष के अंत तक भाजपा की मेजबानी में आईआरआई के शिष्टमण्डल के भारत आने की उम्मीद है ताकि इस सहयोग को और आगे बढ़ाया जाए तथा भाजपा शासित राज्यों के गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर और अधिक जानकारी दी जा सके एवं क्षमता निर्माण पर और अधिक सहयोग किया जा सके। ■

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर विशेष ध्यान देंगे राजनाथ सिंह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कई राज्यों के लिए पार्टी प्रभारी और सह–प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर विशेष ध्यान देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और राष्ट्रीय महासचिव श्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तराखंड के चुनावों हेतु सहयोगी बनाया गया है। राष्ट्रीय महासचिव श्री जगत प्रकाश नड्डा को पंजाब का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली के पूर्व वित्तमंत्री प्रो. जगदीश मुखी को जम्मू–कश्मीर का प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है और अनिल जैन को सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय सचिव श्री श्याम जाजू को हिमाचल प्रदेश तथा श्री नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी के नेता व विधायक श्री रामेश्वर चौरसिया को दिल्ली का सहप्रभारी बनाया गया है। ■

उच्चतम न्यायालय के निर्णय से कांग्रेस हुई बेनकाब : प्रकाश जावडेकर

Hkk जपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री प्रकाश जावडेकर ने 04 जुलाई, 2011 को जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि विदेश में जमा काले धन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा एसआईटी बनाने के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। इस फैसले से कांग्रेस एवं सरकार पूरी तरह से बेनकाब हुई है। सरकार भ्रष्टाचार एवं काले धन के विषय पर सच्चे दिल से कोई ठोस कार्यवाही नहीं करना चाहती है। अब इसका पोल खुल गया है। आज तक जनता सरकार के घोषणाओं पर विश्वास नहीं करती थी अब न्यायपालिका भी सरकार को भरोसेमंद नहीं समझ रही है। आज का निर्णय कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के मुंह पर तमाचा है। यह सरकार की निष्क्रियता का प्रमाण है।

उच्चतम न्यायालय ने काले धन रखने वालों के नाम घोषित करने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ इनके खिलाफ कार्यवाही न करने पर सरकार को लताड़ा है। कोर्ट की यह टिप्पणी कि काला धन हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए धोखा तथा सुरक्षा के लिए खतरा है यह भी महत्वपूर्ण है। कोर्ट का यह आकलन कि विदेश में जितना ज्यादा धन जमा है उतनी सरकार की कमजोरी है यह भी बेहद गम्भीर है। विदेश में जमा सम्पति को वापस लाओ और सम्पति रखने वालों को सजा दिलाओ, इस निर्णय का भी भाजपा ने स्वागत किया है। हसनअली के मामले में कोर्ट को यह तक कहना पड़ा कि कोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार ने सही जांच प्रारम्भ की।

भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के मामले मे गम्भीरता से कोई कदम नहीं उठा रही है। 40 से अधिक देशों के साथ जो कर सम्बंधी विभिन्न संधि हुई है उसमें आने वाले दिनों मे जो काला धन जमा होगा उसकी जानकारी देने की योजना है लेकिन आज तक जो धन वहां जमा हुआ है उसके बारे में जिक्र नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस ने पिछले 60 सालों मे जो लूट हुई है उसको छुपा कर रखने पर अपनी मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि सरकार काला धन रखने वालों की सूची तुरंत जारी करे और आने वाले संसद के अधिवेशन में विदेश के रखे काले धन को राष्ट्रीय सम्पति घोषित करने का कानून लाये।

तेलंगाना की जनता के साथ कांग्रेस का छलावा भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि तेलंगाना राज्य निर्माण के लिये तुरंत बिल संसद मे प्रस्तुत करें और ऐसा करने पर भाजपा ने बिल को पास कराने के लिए और तेलंगाना निर्माण के लिए पूरा साथ देने का भरोसा जताया है।

भारतीय जनता पार्टी मानती है तेलंगाना की जनता के साथ कांग्रेस ने केवल छलावा किया है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने तेलंगाना निर्माण का वायदा किया था और 5 साल में केवल बहाने बनाती रही। प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व में तथाकथित राज्य पुनर्गठन समिति बना कर लोगों को धोखा दिया। 9 दिसम्बर 2009 को केन्द्र सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के स्पष्ट घोषणा के बावजूद पिछले 19 महीने से कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। बेवजह श्रीकृष्ण समिति का निर्माण करके एक साल बर्बाद किया। पृथक राज्य निर्माण के लिए कमेटी के लिए नहीं बिल की जरूरत है। यह भारतीय जनता पार्टी की भूमिका थी और इसलिए पार्टी ने श्रीकृष्ण कमेटी का बहिष्कार किया। आज भारतीय जनता पार्टी की भूमिका सही साबित हुई है इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मांग फिर से दोहराई है।

कांग्रेस की सरकार समय–समय पर सिर्फ झूठे आश्वासन ही देती आई। परन्तु तेलंगाना की जनता को अब भी विश्वास हो गया है कि कांग्रेस सिर्फ धोखेबाज है और झूठे वायदे करती है। कांग्रेस का असली चेहरा जनता के बीच में साफ हो गया है। आज कांग्रेस के खुद के नेता भी इस मामले पर कांग्रेस पर विश्वास नहीं करते है। ■

भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण

रामेश्वरम के पास भारतीय जल सीमा में श्रीलंका नौसेना पुलिस द्वारा 14 भारतीय मछुवारों के गिरफ्तारी की भारतीय जनता पार्टी ने भर्त्सना की है और मांग की है कि इनकी तुरंत रिहाई हो और सरकार इसके लिए खुद सकारात्मक पहल करे। हम चाहते है कि केन्द्र सरकार को श्रीलंका सरकार के साथ इस मसले पर दो टूक बात करनी चाहिए और बार बार इस तरह की श्रीलंका नौ–सेना द्वारा होने वाली कार्रवाई तुरंत रोकने के लिए ठोस उपाय करने चाहिए। याद रहे कि पिछले कुछ महीनों में इसी क्षेत्र मे बार–बार भारतीय मछुवारों को उत्पीड़ित किया जा रहा है।